राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

सीएनएन

कैमी नेट न्यूज

RNI NO. DELHIN/2009/28575

1 से 15 जुलाई 2026 तक

वर्ष-17, अंक 13, नई दिल्ली, संपादक: धर्मेंद्र भदौरिया

पृष्ठ: 8 मूल्य 2/-

मो. 9315605515, 9871167103

Web. : Caiminetnews.in

Email : Cnnkhabar@ Gmail.Com

अमित शाह ने लॉन्च किया एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग पर होगी रियल टाइम निगरानी

■ धर्मेन्द्र भदौरिया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई (इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों डिजिटल पहलों से नागरिकों की सुविधाएं बढ़ेंगी, कागजी कार्यवाही कम होगी और विदेशी अंशदान (एफसीआरए) की रियल टा-इम निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। यहां आयोजित कार्यक्रम में गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिसरी, आसूचना ब्यूरो के विशेष निदेशक महेश दीक्षित तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के विजन के अनुरूप तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एफसीआरए व्यवस्था पहले फाइलों और जटिल प्रक्रियाओं में उलझी हुई थी, लेकिन अब इसका आधुनिकीकरण कर इसे अधिक प्रभावी बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि एफसीआरए 2.0 पोर्टल के जरिए अब आवेदन, नवीनीकरण, वार्षिक विवरणी सहित सभी प्रमुख प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल होंगी। इससे भौतिक रूप से दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तथा ई-साइन आधारित प्रमाणीकरण, ओसीआर (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) आधारित दस्तावेज विश्लेषण और एनजीओ दर्पण सहित विभिन्न सरकारी डाटाबेस से एकीकृत सत्यापन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग पर प्रभावी रियल टाइम निगरानी संभव होगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन दोनों मजबूत होंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में एफसीआरए मोबाइल एप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चैटबॉट और बैंकों के लिए समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड भी शुरू किया जाएगा।

शाह ने ई-ओसीआई कार्ड को भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सुविधा बताते हुए कहा कि इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब 20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट जारी होने पर ओसीआई बुकलेट दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्डधारकों को केवल अपना नया पासपोर्ट विवरण ऑनलाइन अपडेट करना होगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल ओसीआई कार्ड के कारण दस्तावेज खोने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या समाप्त होगी और वास्तविक समय में सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत देश में वर्तमान में करीब 14,500 सक्रिय संगठन पंजीकृत हैं। हर वर्ष लगभग 15,000 से 20,000 नए या नवीनीकरण संबंधी आवेदन तथा करीब 17,000 वार्षिक विवरणियां प्राप्त होती हैं।

एफसीआरए 2.0 पोर्टल को 'मेघराज' (नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड) पर विकसित किया गया है और इसे पैन, आधार, ओसीआई, एनजीओ दर्पण, आईसीएआई की यूडीआईएन प्रणाली तथा बैंकों सहित विभिन्न सरकारी प्रणालियों से जोड़ा गया है। इससे आवेदनों के निपटारे में तेजी आएगी, अनुपालन की निगरानी मजबूत होगी और विदेशी अंशदान के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं, ई-ओसीआई कार्ड व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर कार्ड जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

इससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त होगी, प्रोसेसिंग समय कम होगा, प्रशासनिक लागत में कमी आएगी और हवाई अड्डों पर डिजिटल सत्यापन के माध्यम से यात्रा अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगी।

वेनेजुएला में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत बना सहारा

काराकस। वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत जो फील्ड अस्पताल बनाया है, वहां इलाज करा रहे लोगों ने भारतीय मेडिकल टीम का धन्यवाद किया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को कई वीडियो साझा किए, जिनमें लोग इलाज कराते हुए, अपना अनुभव बताते हुए और भारत की मदद के लिए आभार जताते दिखाई दिए। एक स्थानीय महिला ने इलाज का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। पिछले 60 वर्षों में ऐसी मेडिकल देखभाल नहीं देखी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या अब उनका दर्द कुछ कम हुआ है, तो उन्होंने कहा, हां, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूं। उन्होंने बताया कि इलाज के बाद भारतीय मेडिकल टीम उनके घर वापस जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कर रही है। महिला ने कहा, ₹मैं आपका खास तौर पर धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं किसी तरह लोगों की मदद से यहां तक पहुंची थी और अब आप लोग हमें घर छोड़ने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सच में बहुत आभारी हूं। यहां सब लोग कहते हैं कि धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। यही सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ इतनी शानदार टीम खड़ी है। एंबुलेंस में बैठते समय भी उन्होंने वहां मौजूद भारतीय रक्षा कर्मियों का फिर दिल से धन्यवाद किया। एक दूसरी स्थानीय महिला ने भी भारत की ओर से बनाए गए फील्ड अस्पताल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल इलाके के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। जब उनसे इलाज और डॉक्टरों की सलाह के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ₹हां, मुझे इन दवाइयों के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े। आपकी पूरी मदद के लिए बहुत धन्यवाद।

आपने यहां जो अस्पताल बनाया है, उससे स्थानीय लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं आपके देश की बहुत आभारी हूं। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे। इन भूकंपों में 1,400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और देश के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई। इसके बाद भारत ने राहत और बचाव में मदद के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया। भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री रविवार को वेनेजुएला पहुंच गई। इस मौके पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत की फील्ड अस्पताल यूनिट, राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण वहां चल रहे राहत कार्यों को और मजबूत करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, भारत की सहायता वेनेजुएला पहुंच गई है।

हमें भरोसा है कि फील्ड अस्पताल यूनिट, राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण वहां भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्यों को और मजबूती देंगे। कोटे डी आइवर में भारतीय दूतावास ने भी 'एक्स' पर मिशन की जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि भारतीय वायुसेना के दो सी-17 विमान अबिदजान होते हुए वेनेजुएला पहुंचे। इन विमानों में राहत सामग्री, भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल टीम और दो 'भीष्म क्यूब' भेजे गए। दूतावास ने बताया कि टीम में कुल 41 सदस्य हैं, जिनमें नौ डॉक्टर शामिल हैं। टीम आपातकालीन इलाज, गंभीर चोटों का उपचार, जान बचाने वाली सर्जरी और दूसरी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम अपने साथ लगभग छह टन दवाइयां और दूसरी मानवीय राहत सामग्री भी लेकर गई है।

जापान की प्रधानमंत्री का तीन दिवसीय भारत दौरा: पीएम मोदी के साथ करेंगी शिखर वार्ता

नई दिल्ली। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई, 2026 तक अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत में रहेंगी। इस दौरान वह 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई गति देना है। विदेश मंत्रालय ने जापानी पीएम के कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसके अनुसार, प्रधानमंत्री ताकाइची 1 जुलाई की शाम 7 बजे नई दिल्ली के वायु सेना स्टेशन (एएफएस) पालम पहुंचेंगी, जहां उनका आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। 2 जुलाई को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित होगा। इसके बाद सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), दूरसंचार और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्या रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल सक्रिय, रिपोर्ट में सामने आईं कई गंभीर चुनौतियां

नई दिल्ली। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफ) ने मई 2025 से अब तक 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा किया है। कार्यबल ने 25 हितधारक परामर्श भी आयोजित किए हैं, जिनमें जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, दिव्यांग छात्रों की समस्याएं, एसटी एवं ओबीसी छात्रों के मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इन दौरों और परामर्शों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए छात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए समावेशी और बहु-विषयक नीति तैयार करना है। मंत्रालय के अनुसार अंतरिम रिपोर्ट और अब तक के अध्ययन में कई गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के पीछे केवल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक दबाव, जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक अलगाव, पारिवारिक अपेक्षाएं, पर्याप्त संस्थागत सहयोग का अभाव तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल 70 प्रतिशत से अधिक संस्थानों में पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं मिले। 20 प्रतिशत से भी कम संस्थानों का मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से औपचारिक समन्वय था, जबकि चार प्रतिशत से भी कम संस्थानों में आत्महत्या के जोखिम से निपटने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल मौजूद थे। लगभग 45 प्रतिशत संस्थानों ने पिछले 18 महीनों में शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी आयोजित नहीं किया।

रिपोर्ट के अनुसार 2.43 लाख से अधिक छात्रों के सर्वेक्षण में लगभग 34 प्रतिशत छात्रों ने स्वयं को परिसर में अलग-थलग महसूस करने की बात कही, जबकि 15 प्रतिशत छात्रों ने पिछले छह महीनों में लंबे समय तक अत्यधिक तनाव, अवसाद या चिंता का अनुभव होने की जानकारी दी। वहीं, नौ प्रतिशत छात्रों ने पिछले एक वर्ष के दौरान अक्सर आत्महत्या के विचार आने की बात स्वीकार की।

भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

सौर तूफानों के व्यवहार से अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। भारतीय वैज्ञानिकों ने सूर्य से आने वाले खतरनाक सौर विस्फोटों को लेकर महत्वपूर्ण अध्ययन किया है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी में मदद मिल सकती है। यह शोध भारतीय ख गो ल - भौ ति की संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसमें 1995 से 2024 तक लगभग 30 वर्षों के अंतरिक्ष डेटा का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में बताया गया है कि सूर्य से निकलने वाले इंटरप्लेनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के पास पहुंचकर सैटेलाइट, जीपी एस, रेडियो संचार और बिजली ग्रिड को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में सुंदर ऑरोरा भी उत्पन्न करते हैं। शोध के अनुसार, अब तक यह माना जाता था कि ये सौर विस्फोट अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान लगातार ठंडे हो जाते हैं लेकिन नया अध्ययन इस धारणा को पूरी तरह सही नहीं मानता। वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 45 प्रतिशत आईसीएमई अपने मार्ग में गर्म अवस्था में भी बने रहते हैं।

पश्चिमी दिल्ली में फूड हाइजीन पर सवाल: पीएचआई पर वसूली के आरोप

जनता घटिया खाना खाने को मजबूर, ज्वाला हेड़ी से राजौरी गार्डन तक रेस्टोरेंट-ढाबों में मिलावट का आरोप, निगम अधिकारी पर ड्यूटी के बजाय अवैध उगाही का आरोप

■ धर्मेन्द्र भदौरिया

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता और स्वच्छता पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि दिल्ली नगर निगम, पश्चिमी जोन के हेल्थ विभाग में फूड हाइजीन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात पीएचआई की कथित लापरवाही औऱ लालच के चलते जनता मिलावटी और अनहाइजीनिक खाद्य पदार्थ खाने को मजबूर है। पश्चिमी दिल्ली को खाने-पीने का गढ़ माना जाता है। ज्वाला हेड़ी मार्केट, पंजाबी बाग, मादीपुर, पश्चिम विहार, विकासपुरी, जनकपुरी, उत्तम नगर, महावीर नगर, हरिनगर, सुभाष नगर, राजा गार्डन, राजौरी गार्डन, मानसरोवर गार्डन जैसे इलाकों में हजारों रेस्टोरेंट, ढाबे, रेहड़ी, ठेले, जूस-शेक की दुकानें और टपरियां हैं। जनकपुरी की छोटी मंडी में दर्जनों पनीर निर्माण इकाइयां भी हैं। आरोप है कि इनमें से कई जगह खाद्य सामग्री में रंग, केमिकल और गुणवत्ताहीन सामान का इस्तेमाल हो रहा है।

क्या हैं पीएचआई के अधिकार

डीएमसी एक्ट 1957 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पीएचआई को किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान पर रेड करने, नमूने लेने, फोटो-वीडियो बनाने, नोटिस जारी करने और गंभीर उल्लंघन पर प्रतिष्ठान बंद कराने की सिफारिश करने का अधिकार है। उन्हें स्वच्छता, स्टोरेज तापमान, एक्सपायरी डेट, कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति, एफएसएसएआई लाइसेंस, कचरा निस्तारण और कीट नियंत्रण की जांच करनी होती है।

आरोप: कार्रवाई के बजाय मंथली वसूली

आरोप है कि पीएचआई इंस्पेक्टर अपने अधिकारों का इस्तेमाल जनहित में करने के बजाय प्राइवेट लोगों के जरिये प्रतिष्ठानों से कथित तौर पर मंथली वसूली कर रहे हैं। इसकी वजह से जनता को मिलावटी और प्रतिबंधित केमिकल युक्त खाना खाने को विवश होना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित निरीक्षण न होने से शाकाहारी-मांसाहारी दुकानों, हुक्का बार, बेकरी और हलवाई की दुकानों पर मानकों की अनदेखी हो रही है। निगम का फूड हाइजीन रेड अभियान जनता को अस्वच्छ या मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए होता है, लेकिन आरोप है कि जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। इस मामले में हेल्थ विभाग का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

रीडिंग ब्रांच में चल रही तनातनी, स्पेशल 26 का खौफ अब भी बरकरार?

रामप्रकाश मीणा को सीट से हटाने की कोशिश पर उठे सवाल, आखिर ASO दिलीप कुमार ने क्यों लगाई फटकार?

नई दिल्ली। एनडीएमसी की रीडिंग ब्रांच में एक बार फिर कार्यस्थल की व्यवस्था और सीट आवंटन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने विभाग के कर्मचारियों के बीच कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बताया जाता है कि MIG पद पर कार्यरत रामप्रकाश मीणा अपनी निर्धारित सीट पर बैठकर नियमित कार्यालय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान ASO दिलीप कुमार ने उन्हें कथित रूप से डांटते हुए उस सीट से हटने के लिए कहा। इस घटना के बाद कर्मचारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि अपने निर्धारित स्थान पर कार्य कर रहे कर्मचारी को इस प्रकार फटकार लगाई गई।

क्या सीट को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद?

विभागीय सूत्रों का कहना है कि रीडिंग ब्रांच में सीटों को लेकर पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है। चर्चा है कि एक कर्मचारी पहले ASO की सीट पर बैठने की इच्छा रखता था, लेकिन पदोन्नति के बाद महेश गुर्जर ने अपने अधिकार के अनुसार वह सीट संभाल ली। अब आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि उसी कर्मचारी की नजर रामप्रकाश मीणा को आवंटित MIG सीट पर है। यदि इन दावों में सच्चाई है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसी कर्मचारी को उसकी विधिवत आवंटित सीट से हटाने का प्रयास किस आधार पर किया जा रहा है। रीडिंग ब्रांच में लंबे समय से चर्चित 26 स्पेशल का नाम एक बार फिर कर्मचारियों की चर्चाओं में सामने आ रहा है। विभागीय गलियारों में यह चर्चा है कि कुछ अधिकारी अब भी कथित रूप से इस प्रभाव से मुक्त होकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी को केवल किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव या आशंका के कारण उसकी सीट से हटाने का प्रयास किया गया, तो यह न केवल प्रशासनिक निष्पक्षता बल्कि कार्यस्थल की गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

सीधे-साधे कर्मचारी पर कार्रवाई क्यों?

रामप्रकाश मीणा के बारे में सहकर्मियों का कहना है कि वे शांत स्वभाव के कर्मचारी हैं और अनावश्यक विवादों से दूर रहते हैं। ऐसे में यदि वास्तव में उन्हें सार्वजनिक रूप से डांटा गया, तो यह जानना आवश्यक है कि उसका वैधानिक और प्रशासनिक आधार क्या था। यदि कर्मचारी अपनी आवंटित सीट पर बैठकर नियमित कार्य कर रहा था, तो उसे हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई लिखित आदेश था या केवल मौखिक निर्देश?

सेवानिवृत्ति से पहले उठे सवाल

गौरतलब है कि दिलीप कुमार इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे समय में हुई इस घटना ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों के बीच यह भी चर्चा है कि कहीं किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव या कथित शिकायतों के डर से यह कार्रवाई तो नहीं की गई। ASO दिलीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि उनके विभाग में काम करने का माहौल एकदम पारिवारिक है, छोटी-मोटी शिकायतों को मिल बैठकर सुलझा लिया जाता है।

रामभक्तों पर गोली चलाने वाले आज आस्था की दुहाई दे रहेः सीएम

रामपुर में सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर वार

■ धर्मेन्द्र सिंह चंदेल

रामपुर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। रामपुर में 690 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो लोग कभी रामभक्तों पर गोलियां चलाते थे और 'जय श्रीराम' के नारों का विरोध करते थे, वही आज आस्था की दुहाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर के शाहबाद में करीब 690 करोड़ रुपए की लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का उल्लेख करने के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर तीखे प्रहार किए। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जारी राजनीतिक विवाद का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज वही लोग भगवान राम की भक्ति और आस्था की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले रामभक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाई थीं। उन्होंने कहा, 2017 से पहले जब रामभक्त 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा लगाते थे, तब उन पर गोलियां चलाई जाती थीं। 'जय श्रीराम' बोलने वालों पर लाठियां बरसाई जाती थीं। आज वही लोग आस्था की दुहाई दे रहे हैं। यह जनता की ताकत है कि उन्हें अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन आज अयोध्या जाने की होड़ लगी हुई है। प्रभु श्रीराम सबके हैं और जनता सब कुछ देख रही है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, व्यापारी भय में जीते थे, किसान परेशान थे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्तियां निकलते ही 'चाचा-भतीजे की जोड़ी' वसूली में जुट जाती थी और धांधली के कारण कई भर्तियों पर अदालत को रोक लगानी पड़ती थी। उस दौर में विकास केवल 'एक सैफई परिवार और रामपुर के एक परिवार' तक सीमित था, जबकि गरीब, दलित और आम जनता उपेक्षित रही। आज प्रदेश में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, बेहतर कानून-व्यवस्था और तेज विकास के कारण हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

रामपुर कभी अन्याय की राजनीति के लिए चर्चा में रहता था, लेकिन अब यहां विकास की नई तस्वीर दे रही है दिखाई

रामपुर की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पैचवर्क, वायलिन निर्माण और मेंथा उत्पादन के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। रामपुर कभी जमीन कब्जाने और अन्याय की राजनीति के लिए चर्चा में रहता था, लेकिन अब यहां विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जे की संस्कृति समाप्त हुई है और सरकार बिना भेदभाव सभी तक विकास का लाभ पहुंचा रही है। कांवड़ यात्रा, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले त्योहारों और यात्राओं में बाधाएं खड़ी की जाती थीं, जबकि आज कांवड़ यात्रा से लेकर दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी और अन्य पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और विकास, विरासत तथा सुशासन का नया मॉडल बनकर उभरा है।

यमुना जल समझौते से राजस्थान की प्यासी धरती को मिलेगा पानी: भजनलाल शर्मा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा के साथ हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से राजस्थान के विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र सहित कई जल संकटग्रस्त इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक "ऐतिहासिक कदम" बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कई वर्षों तक राजस्थान के जल संकट को गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि विभिन्न राज्यों और केंद्र में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें रहने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल सका। अब वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और लंबित परियोजनाओं को गति दी जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन अब इस पर प्रगति हो रही है। इसके अलावा 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक "ऐतिहासिक कदम" बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 फरवरी 2024 को हरियाणा सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य राजस्थान को उसके हिस्से का जल सुनिश्चित करना था। इसके बाद 29 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच समन्वय से जल वितरण को लेकर बड़ा समाधान निकाला गया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान के लंबे समय से चले आ रहे जल संकट को गंभीरता से समझा और उसके समाधान के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता परेशान थी। उन्होंने दावा है कि इन समझौतों और परियोजनाओं के लागू होने से आने वाले वर्षों में राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता में सुधार होगा और कृषि व ग्रामीण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ऊर्जा सुरक्षा से औद्योगिक विकास को मिली नई रफ्तार: मनोहर लाल

वडोदरा। केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पश्चिम एशिया में हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा है। यह मजबूती लंबे समय की योजना, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी ढांचे में निवेश के कारण संभव हुई है। वडोदरा में सेंट्रल गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली, आधुनिक शहर और जवाबदेह शासन मिलकर सतत औद्योगिक विकास और निवेशकों के विश्वास की नींव बनाते हैं।

हाल की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तैयारी ने देश को वैश्विक अनिश्चितता से बचाए रखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि पश्चिम एशिया सहित हाल की वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के बावजूद हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखा और मजबूत किया है। हमारी आर्थिक स्थिरता भी बनी रही है। जहां कई देशों में अस्थिरता और उतार-चढ़ाव देखा गया, वहीं भारत ने आत्मविश्वास के साथ स्थिरता बनाए रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण क्षेत्र में किए गए सुधारों से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं।

उन्होंने कहा, "हमने वितरण क्षेत्र में बड़े सुधार लागू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप लंबे समय से घाटे में चल रही वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं और यह क्षेत्र आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ हुआ है, जिससे भविष्य में निवेश के अधिक अवसर बने हैं।" मनोहर लाल ने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेशक अब शहरों की सेवाओं की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हैं।

उन्होंने कहा, "जब कोई निवेशक किसी राज्य का चयन करता है, तो वह केवल प्रोत्साहन योजनाओं को नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि वहां कर्मचारियों के लिए आवास, परिवहन, पानी, सीवरेज, डिजिटल गवर्नेंस और स्वच्छता जैसी सुविधाएं कैसी हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शहरी विकास को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा है और शहरों को विकास, नवाचार और रोजगार के केंद्र के रूप में देखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि देशभर में 1.27 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 98.65 लाख घर पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में 11.5 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 10 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। अमृत योजना के तहत गुजरात को 28 लाख नए पेयजल कनेक्शन और 42.47 लाख सीवरेज कनेक्शन मिले हैं। मंत्री ने भारत के शहरी परिवहन नेटवर्क पर भी प्रकाश डाला और बताया कि अब 29 शहरों में मेट्रो रेल सेवा चालू है।

उन्होंने कहा, "भारत में आज 1,155 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।" उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शहरी आवागमन में तेज गति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वित्तीय समावेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 76 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा, "40 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपना ऋण समय पर चुका दिया है और अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। लगभग 8 लाख लोग तीनों चरणों के लोन का लाभ लेकर अब पीएम मुद्रा जैसी बड़ी योजनाओं की ओर बढ़ चुके हैं।" मंत्री ने कहा कि बेहतर आवास, परिवहन और शहरी सेवाएं सीधे औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाती हैं। उन्होंने गुजरात की शहरी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा कि अहमदाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर और सूरत को सुपर स्वच्छता लीग में स्थान मिला है। मनोहर लाल ने गुजरात को भारत के विकास मॉडल का उदाहरण बताते हुए कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति, उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई, हरित विकास, नवाचार और महिला नेतृत्व विकास इसे निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाते हैं।

उन्होंने निवेशकों को गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार और निवेशकों के बीच संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होने चाहिए।

गुंडागर्दी करने वालों की संपत्ति होगी जब्त, 1 साल की होगी जेल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार दोपहर पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण बिल, 2026 बहुमत से पास किया गया। इस बिल का मकसद राज्य में भ्रष्टाचार, असामाजिक और उपद्रवी गतिविधियों को रोकना है। सत्ताधारी भाजपा खेमे से 176 विधायकों ने बिल के पक्ष में वोट किया। 41 विधायकों ने बिल के खिलाफ वोट किया, जबकि बाकी 20 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।

जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संगठित असामाजिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखने के मकसद से लाए गए इस बिल की खासियत यह है कि यह असामाजिक गतिविधियों से निपटने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के अलग-अलग प्रावधानों से दो मुख्य बातों में अलग है।

पहली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जनता की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो कानून बनने के बाद यह बिल उसे एक साल तक के लिए 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' (एहतियाती हिरासत) में रखने की इजाजत देगा। दूसरी बात यह है कि यह राज्य सरकार को ऐसे अपराध में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, जिसके लिए बीएनएस के संबंधित प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पहले प्रावधान यानी 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' को लागू करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड तय करेगा कि किसी खास व्यक्ति को हिरासत में रखना सही है या नहीं। एडवाइजरी बोर्ड 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' के औचित्य की जांच करेगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा। एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा या पूर्व जज होंगे। इसमें दो अन्य सदस्य भी होंगे जो हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों।

नया कानून पुलिस को यह अधिकार भी देगा कि अगर उन्हें शक हो कि कोई व्यक्ति अशांति फैला सकता है, तो वे उसे किसी खास इलाके से निकाल सकते हैं या वहां आने से रोक सकते हैं। यह कानून इसे लागू करने में शामिल पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को भी सुरक्षा देगा। इतना कड़ा बिल लाने की जरूरत पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सदन में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली और तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान हुई गुंडागर्दी और हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' को लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी दूर किया और कहा कि यह प्रावधान 'सज्जन लोगों' के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है।

मुख्यमंत्री ने की पटना मेट्रो परियोजना की समीक्षा, 2 जुलाई को होगा लोकार्पण

पटना मेट्रो परियोजना समयसीमा में पूरी करें, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं : मुख्यमंत्री

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 जुलाई 2026 को पटना मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार मलाहीपकड़ी तक आम जनता को समर्पित किया जाएगा। इस विस्तार के शुरू होने से राजधानीवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी, यात्रा का समय कम होगा और शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनेगी।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभिन्न निर्माण स्थलों पर समानांतर रूप से तेजी से कार्य करने, नियमित मॉनिटरिंग तथा सतत समीक्षा के माध्यम से परियोजना को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने मेट्रो निर्माण के दौरान आम लोगों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने के लिए प्रभावी एवं वैज्ञानिक ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही पूरे पटना शहर की यातायात व्यवस्था का व्यापक अध्ययन कर जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए समग्र ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना मेट्रो के संचालन से राजधानीवासियों को सुरक्षित, तेज, आधुनिक और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

नीमच के सोलर प्लांट से मिलेगी देश की सबसे सस्ती बिजली: सीएम मोहन यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नीमच में नए सोलर पार्क का शुभारंभ ऐतिहासिक अवसर है। इससे देश में सबसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क तथा 450 मेगावॉट क्षमता वाले शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि नीमच के सोलर प्लांट से दो रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी जो देश में सबसे सस्ती होगी। प्रदेश का हरित विकास हमारा लक्ष्य है। हरित विकास के जरिए प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में निवेश लाने और इसके जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अब स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा से इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के नए औद्योगिक ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहे हैं। नीमच न केवल मध्य प्रदेश का, बल्कि ग्रीन पॉवर सेक्टर का ग्लोबल कैपिटल बन रहा है। उन्होंने बताया कि यहां देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज बन रहा है। नीमच जिले में कुल 675 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं कार्यशील हैं और लगभग 1 हजार 952 से अधिक मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत 19 मार्च से 30 जून तक कुंए, बावड़ी, नदी, तालाब और अन्य सभी जल स्त्रोतों के संरक्षण के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य सरकार ने 3 महीने में 10 हजार करोड़ की राशि खर्च कर प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार किया है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की मौजूदगी में आज 2 बड़ी सौर परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। कुल 2080 करोड़ की लागत से नीमच में 500 मेगावॉट और शाजापुर में 450 करोड़ मेगावॉट के सोलर पार्क की सौगात मिली है। साथ ही नीमच में 1553.98 करोड़ की 38 औद्योगिक इकाइयों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी हुआ है। नीमच के नए सोलर पार्क से 2.14 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जो देश में सबसे सस्ती दर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार देने वाला राज्य है। प्रदेश में फूड पार्क, पीएम मित्र पार्क तैयार किए जा रहे हैं। नीमच में 1200 करोड़ से अधिक लागत का सोलर ग्लास तैयार करने वाले प्लांट का भूमि-पूजन हुआ है। नीमच को बहुत जल्द जावरा-उज्जैन होकर भोपाल राजमार्ग की सौगात मिलने वाली है। मंदसौर से भोपाल तक नया हाई-वे भी बनाया जाएगा। नीमच में गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया घर बन चुका है। बहुत जल्द यहां दो और चीते मुक्त प्राकृतिक आवास में छोड़े जाएंगे।

दिल्ली कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी 2026 को दी मंजूरी

दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ सस्ता, 1 लाख तक का इंसेंटिव, रोड टैक्स माफ

■ धर्मेंद्र भदौरिया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति 1 जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देकर राजधानी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है।

नीति के मुख्य प्रावधान

श्रेणी	प्रावधान
कुल बजट: खरीद प्रोत्साहन 1,500 करोड़, स्क्रैपेज लाभ 1,500 करोड़, चार्जिंग इंफ्रा 1,000 करोड़, टैक्स-छूट 3,000 करोड़	
खरीद प्रोत्साहन	*ई-टू व्हीलर 30,000 तक* *ई-थ्रीव्हीलर 50,000 तक* *N-1 ई-ट्रक 1 लाख तक*
टैक्स छूट	*रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन शुल्क 100% माफ। ई-कारों पर 30 लाख एक्स-शोरूम तक छूट*

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्क्रैपिंग पर भी फोकस

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी विशेष ध्यान देती है। उन्होंने कहा, "सब्सिडी की व्यवस्था इस तरह तैयार की गई है कि पारंपरिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच लागत का अंतर कम किया जा सके।"

15,000 करोड़ रुपए के लाभ का दावा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा। इसके अलावा ईवी उपयोगकर्ताओं को 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट और विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह नीति उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की औपचारिक मंजूरी के बाद लागू होगी।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट

नई नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 30 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इस लाभ के पात्र होंगे।

सभी श्रेणी के वाहनों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, हल्के मालवाहक ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है।

मंत्रियों को दी बधाई

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह, आशीष सूद और मंजिंदर सिंह सिरसा को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल कर शहर के परिवहन तंत्र में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार द्वारा समर्थित एक अध्ययन के अनुसार, राजधानी में वाहनों से होने वाले कुल प्रदूषण का 33% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से और 46% हिस्सा दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों से आता है। नई ईवी नीति का उद्देश्य इन श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना है।

30 जून से दिल्ली में SIR की 'दस्तक'

BLO पहुंचेंगे घर-घर, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

■ नरेन्द्र भंडारी

नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आपके दरवाजे पर चुनाव आयोग की घंटी बज सकती है। दिल्ली में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार के मुताबिक, पूरे 21 साल बाद दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर यह खास अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है, या उसमें कोई गलती है, तो आपके पास इसे ठीक कराने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। दिल्ली में लगभग 13 हजार बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) 30 जून से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार में घर पर नहीं मिलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीम आपके घर कम से कम 3 बार विजिट करेगी।

मिलेगा न्यूमिरेशन फॉर्म: सर्वे के दौरान आपको दो 'न्यूमिरेशन फॉर्म' दिए जाएंगे। एक फॉर्म आपको भरकर BLO को देना होगा और दूसरा अपने पास संभालकर रखना होगा।

दस्तावेजों का झंझट नहीं: इस फॉर्म को जमा करते समय आपको किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है।

ऑनलाइन भी है सुविधा: यदि आप काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं या शहरी इलाके में हैं, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

क्यों हो रहा है यह सर्वे?

इसका मकसद उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। साथ ही, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए युवाओं के नाम जोड़े जाएंगे।

कैलेंडर पर नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

वोटर लिस्ट में सुधार और नए नाम जोड़ने का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार तय किया गया है:

तारीख क्या होगा?

30 जून घर-घर जाकर डोर-टू-डोर सर्वे और वेरिफिकेशन की शुरुआत।

5 अगस्त वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट (प्रारूप) का प्रकाशन।

7 अक्टूबर सभी सुधारों और दावों के निपटारे के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

21 साल बाद ऐसा क्यों?

इससे पहले दिल्ली में इस स्तर का स्पेशल रिवीजन साल 2002-2004 में हुआ था। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साल 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि लोग पुरानी डिटेल्स भी चेक कर सकें। इसके अलावा, चुनाव आयोग पोलिंग बूथ्स को भी व्यवस्थित कर रहा है और अब एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1,200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे, जिससे वोटिंग के दिन लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। जनता की मदद के लिए दिल्ली के सभी जिलों में जल्द ही विशेष कैंप और हेल्पडेस्क भी लगाए जाएंगे।

सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बनाए 20 तकनीकी प्रोटोटाइप, 'टेक4फ्यूचर' बूटकैंप का समापन

देवेन्द्र पंवार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के CM SHRI स्कूलों के 100 मेधावी विद्यार्थियों ने शनिवार को IIIT-दिल्ली में आयोजित 'टेक4फ्यूचर इनोवेशन शोकेस' में स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक नवाचार से जुड़े 20 कार्यशील तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह तीन सप्ताह के गहन STEM और रोबोटिक्स बूटकैंप का समापन समारोह था, जहां बच्चों ने एआई, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर काम किया।

चार बड़े संस्थानों से ऐतिहासिक करार

इस मौके पर शिक्षा निदेशालय ने DTU, DSEU, IGDTUW और IIIT-दिल्ली के साथ तीन साल के समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। जून 2026 से लागू इन समझौतों के तहत इन संस्थानों के प्रोफेसर और शोधार्थी CM SHRI स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को निःशुल्क मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम सहयोग और अत्याधुनिक लैब्स की सुविधा देंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, यह पहल NEP-2020 को जमीन पर उतारने का उदाहरण है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से नहीं, उनकी क्षमता और नवाचार से आगे बढ़ेगी।

CM SHRI स्कूलों से 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन बहु-स्तरीय प्रक्रिया से किया गया। इन्हें 20 टीमों में बांटकर 140 घंटे से ज्यादा का प्रशिक्षण दिया गया। IIIT-दिल्ली के मेकर स्पेस, 3D प्रिंटिंग लैब और एडवांस्ड फैब्रिकेशन लैब में बच्चों ने समस्या की पहचान से लेकर प्रोटोटाइप बनाने और टेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया सीखी। केवल रोबोटिक्स तक सीमित नहीं सूद ने बताया कि यह साझेदारी वित्त, मानविकी, मीडिया और विधि अध्ययन तक विस्तारित होगी। बच्चों को विश्वस्तरीय रिसर्च लैब, 3D प्रिंटिंग और स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्रों तक सीधी पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य के लिए तकनीकी रूप से दक्ष और नवाचार-आधारित कार्यबल तैयार करने की दिशा में अहम है।

गौतमपुरी हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले जय भगवान गोयल

नई दिल्ली। गौतमपुरी में नाबालिग लक्की की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार ने गोयल से मांग की कि हत्या के आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। गोयल ने परिवार को आश्वासन दिया कि उनकी मांग केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

बुलडोजर मॉडल लागू करने की मांग

गोयल ने कहा, दिल्ली में भी आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी मॉडल की तर्ज पर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा संगठित अपराध में शामिल तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है।

प्रशासन से सुरक्षा की मांग

गोयल ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा, न्याय और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा, कानून के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। किसी भी निर्दोष नागरिक की हत्या लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंताजनक है और दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाना आवश्यक है। गौरतलब है कि गौतमपुरी में लक्की की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है।

7 जुलाई को आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफ़लाइन काउंसलिंग

नई दिल्ली। आईपी यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ (बीएमएस) प्रोग्राम में दाख़िले के लिए पहली ऑफ़लाइन काउंसलिंग 7 जुलाई को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी। उसी दिन आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत मेरिट के आधार पर सीटों का भी आवंटन कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवार इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी कुलसचिव के नाम से निर्गत 96 हज़ार रुपये का बैंक ड्राफ्ट, चार पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, सीईटी का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, ऑनलाइन भरा हुआ फ़ॉर्म,जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, इत्यादि साथ लाना हैं। 142 कोड वाले इस प्रोग्राम की काउंसलिंग के बाद आवंटित सीट 14 जुलाई तक निरस्त किए जा सकते हैं। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से संबद्ध-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पैकेजिंग (60 सीटें) में उपलब्ध है। इस काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी आवेदक इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट करें।

दिल्ली में नए जिलों के हिसाब से अधिकारियों को मिले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार

उदय कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली में राजस्व जिलों के नए सिरे से गठन के बाद एलजी टीएस संधू ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की मंजूरी दे दी है। अब नए जिलों के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), राजस्व सहायक, तहसीलदार और बंदोबस्त अधिकारियों को ये कानूनी अधिकार मिल जाएंगे।

यह फैसला नए कानून "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023" की धारा 14 के तहत लिया गया है, जिसने पुराने सीआरपीसी की जगह ली है।

एलजी की मंजूरी के बाद जारी होगा आधिकारिक नोटिफिकेशन, दिल्ली में 25 दिसंबर 2025 को जिलों का नया ढांचा तैयार किया गया था, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कामकाज को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए अधिकारियों को ये अधिकार देना जरूरी हो गया था। इस प्रस्ताव को दिल्ली के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। अब उपराज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देगी।

करोल बाग में जुए का अड्डा पकड़ा, 13 जुआरी गिरफ्तार

नई दिल्ली। मध्य जिला की स्पेशल स्टाफ टीम ने करोल बाग इलाके में चल रहे अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़ कर आयोजक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से दांव पर लगी 47,150 रुपये नकद राशि और ताश की तीन गड्डियां बरामद की हैं। 22 जून 2026 को स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली कि जगजीवन निवास, करोल बाग स्थित मकान नंबर 41/23, गली नंबर 2, चौथी मंजिल पर 12-13 लोग ताश के पत्तों पर रमंग पट्टार नाम से ऑफलाइन सट्टा लगा रहे हैं। सूचना पर इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में एएसआई प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल मुनेश शर्मा, विकास, विनय, कांस्टेबल नितिन और सूरजपाल की टीम गठित की गई। टीम ने एसीपी ऑपरेशंस पदम सिंह राणा की देखरेख में जाल बिछाकर छापा मारा। दरवाजा खुलते ही पुलिस ने अंदर दबिश दी और 13 लोगों को रंगे हाथ ताश पर नकद दांव लगाते हुए पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान तलवीर सिंह (त्रिलोकपुरी), रूप सिंह, कमल धामी, पूरन गोरखा, खड़क रावत, मोती सिंह (सभी करोल बाग), भक्त बहादुर, लाल बहादुर (जिला अछाम, नेपाल), राजेंद्र लोहार (जिला बाजुरा, नेपाल), जेसे सौद (गुरुग्राम), नंदा बूढ़ा (तिगरी), नीरज बोगटी (पीतमपुरा) और शेरा (महरौली) के रूप में हुई है।पूछताछ में सभी आरोपियों ने रमंग पट्टार पद्धति से जुआ खेलने की बात कबूली। पुलिस के अनुसार पूरन गोरखा इस अड्डे का आयोजक था और वही अपने कमरे को जुए के लिए उपलब्ध कराता था।

दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस मुठभेड़

2 लाख का इनामी बदमाश साथी समेत काबू

नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने नजफगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद दो लाख रुपये के इनामी कुख्यात बदमाश रोहित लांबा और उसके साथी रितिक ठाकुर को गिरफ्तार किया है।

मुठभेड़ में रोहित लांबा के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्तौल, मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखे बरामद किए हैं। डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह, आईपीएस और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा, आईपीएस के नेतृत्व में जिले में नो गन्स, नो गैंग्स अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत थाना नजफगढ़ की टीम अवैध हथियार और गैंग पर लगातार कार्रवाई कर रही है। 28 जून 2026 को एफआईआर नंबर 293/2026 की जांच के दौरान एसआई दीपक शर्मा को सूचना मिली कि वांछित बदमाश रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और रितिक ठाकुर, शक्ति नगर एक्सटेंशन स्थित साईं बाबा मंदिर के पास छिपे हैं। एसएचओ सही राम मीणा और इंस्पेक्टर ओमप्रकाश बिश्नोई के पर्यवेक्षण में एसआई दीपक शर्मा, एसआई हिमांशु, एसआई पंकज, एचसी हवा सिंह, कांस्टेबल आशीष व रवि प्रकाश की टीम बनाई गई। सुबह 6 बजे टीम ने छापा मारा। रोहित लांबा भागने लगा जिसे पीछा कर दबोच लिया गया। साथी रितिक ठाकुर को अंदर से पकड़ा गया।

गोल्फ लिंक बनी एनडीएमसी की नौवीं 'अनुपम कॉलोनी'

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने जीरो वेस्ट एवं सतत विकास अभियान के तहत गोल्फ लिंक को नौवीं "अनुपम कॉलोनी" के रूप में प्रमाणित किया है। बुधवार को एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कॉलोनी में शिलापट्ट का अनावरण किया।

चंद्रा ने कहा, नौ अनुपम कॉलोनियों की उपलब्धि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एवं सतत जीवनशैली के प्रति एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि गोल्फ लिंक ने स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण को प्रभावी रूप से अपनाया है। यहां रीसाइक्लिंग योग्य सामग्री को रीसाइक्लिंग केंद्रों तक भेजा जा रहा है और गीले कचरे से बनी खाद को कॉलोनी में बागवानी के लिए उपयोग किया जा रहा है।

एनजीओ के साथ साझेदारी

गोल्फ लिंक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय माथुर ने कहा कि 'जीरो वेस्ट कॉलोनी' की परिकल्पना को निवासियों के सामूहिक प्रयासों से हकीकत बनाया गया है। संयुक्त सचिव नम्रता खन्ना ने बताया कि एनजीओ 'चिंतन' के सहयोग से सतत कूड़ा प्रबंधन और इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन (आईपीसीए) के साथ मिलकर प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान किया जा रहा है।

सनातन व नारी सम्मान पर बड़ी लकीर खींचते योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म तथा स्त्री गरिमा तथा सम्मान के हित में बड़ी रेखाएं खींच रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने केआदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गयी है। मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कहा है कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। हम उन संस्कारों में पले -बढ़े हैं जहां गांव की बेटी-बहन को पूरे गांव की बेटी -बहन माना जाता है।

मुख्यमंत्री योगी बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पवान हैं। वह कई जनसभाओं मे अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो अगले चैराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी जी के बयानों का असर धरातल पर भी दिखाई पड़ता है। बेटियों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहे हैं। प्रदेश में नारी समाज को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं।

सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रवैया दिखाकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बुने जा रहे चक्रव्यूह को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश की बेटी अदिति पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जो एक्शन लिया है उसने इस दुखद घटना पर बनाए जा रहे सपा के राजनैतिक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से यह विवाद बड़े राजनीतिक तूफान में बदल रहा था और सपा योगी जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहकर घेरने का प्रयास कर रही थी कि, "जिनका खुद का परिवार नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे" तब योगी जी इस घटना के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ रहे थे। योगी जी ने अपराधियों पर तुरंत एफआईआर कराने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह किसी भी बेटी क्यों न हो बेटी पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। योगी की पाती दे रही सनातन विचार-विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरुकता दिवस पर योगी जी ने एक पाती जारी की है। इस पाती में उन्होंने वृद्धजनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि उम्र के अमृतकाल में वृद्धजनों को अपनत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, दुर्भाग्य से समाज ऐसे समय का साक्षी बन रहा है जब वृद्धजनों को अपनों का दुर्व्यवहार सहना पड़ता है।

योगी जी ने आगे लिखा है कि सनातन संस्कृति में माता-पिता और गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है। पाती में योगी ने एक प्राचीन कथा के माध्यम से इस विषय को समझाया। भगवान शिव-पार्वती ने पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय के समक्ष समस्त जगत की परिक्रमा की चुनौती रखी। भगवान गणेश ने माता-पिता को ही संपूर्ण सृष्टि मानकर उनकी परिक्रमा कर ली। उन्होंने भगवान श्रीराम का भी उदाहरण दिया। योगी जी का स्पष्ट कहना है कि सनातन, धार्मिक तथा सामाजिक परंपराओं, पारिवारिक संबंधों एवं मूल्यों पर आधारित जीवन शैली है।

यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कदम से सिद्ध कर दिया है कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है। इससे सपा मुखिया रक्षात्मक रुख अपनाने को बाध्य हो गए हैं। अब भाजपा सपा के पुराने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर उस पर हमलावर है। जो मुद्दा सरकार को घेरने के लिए तैयार किया जा रहा था उस पर योगी जी की प्रशासनिक और राजनीतिक सूझबूझ का बुलडोजर चल गया है। समाजवादी पूर्व में कई बार नारी सम्मान व उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी करते रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि "लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। सपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खां जैसे नेता तो कई बार महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। मायावती जी पर तो सपाइयों ने हमला ही बोल दिया था। सपा राज में महिला सुरक्षा की कितनी बुरी स्थिति थी यह हर कोई जानता है।

सनातन में बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की परंपरा है ऐसा इसलिए क्योंकि वे हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के धरोहर हैं। वृद्धजनों का सम्मान केवल संस्कर नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली सभ्यता की पहचान है। अपनी पाती मे वह बता रहे हैं कि वृद्धजन व निराश्रित महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है।

अग्नि-जाल में बदलते शहरी भवन

■ उदय कुमार

भारत आज विश्व के सबसे तेज़ी से शहरीकरण करने वाले देशों में शामिल है। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, सेवा क्षेत्र के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर निरंतर हो रहे पलायन ने भारतीय शहरों का स्वरूप तेजी से बदला है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक बहुमंजिला इमारतें, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कोचिंग संस्थान, होटल, अस्पताल और मिश्रित-उपयोग वाले भवन विकास के नए प्रतीक बनकर उभरे हैं। किंतु इस विकास के पीछे एक गंभीर सच्चाई भी छिपी है—शहरी नियोजन की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की उपेक्षा और प्रशासनिक शिथिलता। परिणामस्वरूप, आज अनेक शहरी भवन आर्थिक प्रगति के केंद्र होने के साथ-साथ संभावित अग्नि-जाल भी बनते जा रहे हैं।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि-दुर्घटनाओं ने इस संकट की भयावहता को उजागर किया है। दिल्ली, लखनऊ, सूरत, कोलकाता, हैदराबाद की व्यावसायिक इमारतों, होटलों, कोचिंग संस्थानों और मुंबई के अस्पतालों में लगी आग ने सैकड़ों परिवारों को असमय शोक में डुबो दिया। अधिकांश घटनाओं में एक जैसी कमियाँ सामने आईं- भवनों का अनधिकृत उपयोग, अग्नि-सुरक्षा उपकरणों का अभाव, बंद या अवरुद्ध आपातकालीन निकास, संकरी सड़कें, अवैध पार्किंग और नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या किसी एक भवन, किसी एक शहर या किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि हमारे पूरे शहरी विकास मॉडल की है।

भारत में मिश्रित-उपयोग वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक ही भवन में नीचे दुकानें, ऊपर कार्यालय, उसके ऊपर कोचिंग संस्थान और सबसे ऊपर आवास होना अब सामान्य बात है। यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभकारी अवश्य प्रतीत होती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण है। ऐसे भवनों में ज्वलनशील सामग्री, विद्युत उपकरण, गैस सिलेंडर, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति और सीमित निकास मार्ग आग लगने की स्थिति में उसे विनाशकारी बना देते हैं। यदि भवन मूल रूप से आवासीय उद्देश्य के लिए निर्मित हो और बाद में बिना संरचनात्मक परिवर्तन के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाए, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

अनियोजित शहरीकरण इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। भारत के अधिकांश शहर बिना दीर्घकालिक मास्टर प्लान के फैलते गए। आबादी बढ़ती गई, लेकिन सड़कें नहीं बढ़ीं; भवन ऊँचे होते गए, परंतु अग्निशमन सेवाओं की क्षमता उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। अनेक पुराने बाजारों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन तक प्रवेश नहीं कर पाते। कई स्थानों पर बिजली के तारों का जाल, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण आग पर नियंत्रण की प्रक्रिया को और कठिन बना देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ ही मिनटों में छोटी आग भी बड़ी त्रासदी में बदल जाती है।

इस संकट का दूसरा महत्वपूर्ण कारण नीतिगत विरोधाभास है। एक ओर सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुमतियों की प्रक्रिया सरल बना रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा। कई राज्यों में निश्चित ऊँचाई तक के भवनों को अनिवार्य अग्नि-अनापत्ति प्रमाण-पत्र से छूट प्राप्त है। परिणामस्वरूप हजारों ऐसे भवन बिना नियमित अग्नि-सुरक्षा निरीक्षण के संचालित होते रहते हैं। कई बार भवन निर्माण की अनुमति एक उद्देश्य के लिए मिलती है, किंतु समय के साथ उसका उपयोग पूरी तरह बदल जाता है। दुर्भाग्य से इस परिवर्तन की प्रभावी निगरानी करने वाली कोई मजबूत प्रणाली विकसित नहीं हो सकी है।

प्रशासनिक समन्वय का अभाव भी स्थिति को जटिल बनाता है। भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम देता है, भूमि उपयोग परिवर्तन विकास प्राधिकरण देखता है, व्यापार लाइसेंस किसी अन्य विभाग से जारी होता है और अग्नि-सुरक्षा का दायित्व अग्निशमन विभाग पर होता है। इन विभागों के बीच सूचनाओं का समुचित आदान-प्रदान नहीं होने से नियमों का प्रभावी अनुपालन नहीं हो पाता। कई बार भवन निर्माण के समय सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में भवन में किए गए अवैध परिवर्तन वर्षों तक किसी की निगाह में नहीं आते।

भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव भी इस समस्या का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रह जाएँ और प्रमाण-पत्र वास्तविक जाँच के बिना जारी होने लगें, तो नियमों का अस्तित्व मात्र औपचारिकता बनकर रह जाता है। अनेक दुर्घटनाओं के बाद यह सामने आया कि भवनों में अग्निशामक यंत्र तो लगे थे, किंतु उनकी समय-समय पर जाँच नहीं हुई थी। कई स्थानों पर स्प्रिंकलर प्रणाली कार्य नहीं कर रही थी या आपातकालीन निकास पर ताले लगे हुए थे। यह केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक और नैतिक विफलता भी है। नागरिक जागरूकता की कमी भी इस संकट को बढ़ाती है। अधिकांश लोग भवन खरीदते या किराए पर लेते समय अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था की जाँच नहीं करते। व्यापारिक प्रतिष्ठान लागत कम करने के लिए सुरक्षा उपकरणों की उपेक्षा करते हैं। नियमित मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और आपातकालीन निकासी अभ्यास को अनावश्यक समझा जाता है। जबकि विकसित देशों में अग्नि-सुरक्षा संस्कृति को विद्यालय स्तर से ही बढ़ावा दिया जाता है।

भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पिछले दो दशकों में काफी मजबूत हुई है, लेकिन आग जैसी शहरी आपदाओं की रोकथाम पर अपेक्षित ध्यान अभी भी नहीं दिया गया है। आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्यों में हमारी संस्थाएँ उल्लेखनीय कार्य करती हैं, किंतु यदि रोकथाम और जोखिम न्यूनीकरण पर समान गंभीरता से निवेश किया जाए तो अनेक त्रासदियों को रोका जा सकता है। आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत भी यही है कि रोकथाम पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया राहत और पुनर्वास पर होने वाले कई गुना व्यय को बचाता है। अब आवश्यकता केवल दंडात्मक कार्रवाई की नहीं, बल्कि व्यापक संरचनात्मक सुधारों की है। सबसे पहले शहरी नियोजन को वैज्ञानिक और भविष्य-दृष्टि वाला बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक शहर में भूमि उपयोग, जनसंख्या घनत्व, सड़क चौड़ाई, जल स्रोत, अग्निशमन केंद्रों की स्थिति और आपातकालीन पहुँच मार्गों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मिश्रित-उपयोग वाले क्षेत्रों के लिए अलग सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाएँ और भवनों की स्वीकृति इन्हीं मानकों के अनुरूप हो।

दूसरा, राष्ट्रीय भवन संहिता से अग्नि-सुरक्षा मानकों का देशभर में समान रूप से कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भवन की ऊँचाई के बजाय उसमें उपस्थित लोगों की संख्या, गतिविधि की प्रकृति और अग्नि-जोखिम के आधार पर सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। सभी सार्वजनिक और मिश्रित-उपयोग भवनों में स्वचालित स्प्रिंकलर, धुआँ संवेदक, अग्नि-अलार्म, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और स्पष्ट निकास मार्ग अनिवार्य हों। तीसरा, भवनों की स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस, फायर लाइसेंस और निरीक्षण को एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाए। यदि किसी भवन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य से भिन्न पाया जाए या उसका सुरक्षा प्रमाण-पत्र समाप्त हो जाए तो संबंधित विभागों को स्वतः सूचना प्राप्त हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग कर जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

चौथा, अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक उपकरण, ऊँची इमारतों तक पहुँचने वाली हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ, पर्याप्त जल स्रोत, प्रशिक्षित मानव संसाधन और तेज़ प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जाए। छोटे और मध्यम शहरों में भी अग्निशमन अवसंरचना को जनसंख्या और भवनों की संख्या के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए। पाँचवाँ, नागरिक सहभागिता को नीति का अभिन्न अंग बनाया जाए। विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों, अस्पतालों और आवासीय सोसाइटियों में नियमित अग्नि-सुरक्षा प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल अनिवार्य किए जाएँ। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान ने जनभागीदारी को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि-सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

अंततः, शासन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी दुर्घटना का कारण नियमों का उल्लंघन या निरीक्षण में लापरवाही हो, तो केवल भवन मालिक ही नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी स्पष्ट जवाबदेही तय हो। पारदर्शिता, नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण और स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं। भारत के शहर केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, सपनों और भविष्य के आधार हैं। यदि शहरी विकास सुरक्षा, नियोजन और उत्तरदायित्व से रहित होगा, तो विकास का यही मॉडल बार-बार मानवीय त्रासदियों को जन्म देता रहेगा। आवश्यकता ऐसी शहरी संस्कृति विकसित करने की है जिसमें भवनों की ऊँचाई से अधिक महत्व उनकी सुरक्षा को मिले, व्यावसायिक लाभ से अधिक प्राथमिकता मानव जीवन को दी जाए और नियमों का पालन बाध्यता नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाए।

वास्तविक स्मार्ट सिटी वही होगी जहाँ नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, जहाँ भवन विकास के प्रतीक होने के साथ-साथ सुरक्षा के भी मानक बनें और जहाँ प्रत्येक निर्माण यह संदेश दे कि मानव जीवन किसी भी आर्थिक लाभ से अधिक मूल्यवान है। यदि भारत को भविष्य के सुरक्षित, टिकाऊ और आपदा-प्रतिरोधी शहर बनाने हैं, तो प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों से आगे बढ़कर दूरदर्शी शहरी नियोजन, कठोर नियामकीय व्यवस्था, आधुनिक तकनीक, पारदर्शी प्रशासन और जागरूक नागरिक सहभागिता पर आधारित दीर्घकालिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। तभी विकास की चमक के पीछे छिपे अग्नि-जाल को समाप्त कर सुरक्षित और संवेदनशील शहरी भारत का निर्माण संभव होगा।

जाति, धर्म और आरक्षण

हृदयनारायण दीक्षित

मतांतरण से आरक्षण नहीं मिलता। इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति अपना मत बदल कर मुसलमान हो सकता है लेकिन पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं रह जाता। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ईसाई मिशनरियों और इस्लामी उपदेशकों ने सदियों तक अपने-अपने पंथ की प्रशंसा की है कि उनके यहां सामाजिक समता है। बराबरी है। भेदभाव नहीं है। हिन्दुओं में जाति व्यवस्था है। कोर्ट ने कहा है कि उसका मत है कि कुछ वर्गों को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा बताना कुरान की शिक्षा के विपरीत है। फिर इस्लाम का तो दावा ही बराबरी वाला समाज बनाना है। बहुत लम्बे समय से ईसाई और इस्लामी धर्म उपदेशक धर्मांतरित व्यक्ति के लिए भी पिछड़े वर्गों की सुविधाएं मांगते रहे हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं और फैसले सुनाए हैं। लेकिन राजनीतिक दलतंत्र द्वारा धर्मांतरित व्यक्ति के लिए भी आरक्षण की सुविधा मांगी जाती रही है। इस दफा न्यायालय ने साफ कर दिया है कि सिर्फ मतांतरण करने से किसी व्यक्ति का वर्ग नहीं बदलता और मतांतरित व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं माना जा सकता।

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मार्च 2024 के आदेश को असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। सरकारी आदेश में मतांतरण करने वाले व्यक्ति को मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का सदस्य माना गया था। मतांतरित व्यक्ति को भी पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया था। यह चर्चित फैसला मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने 25 जून को सुनाया है। कोर्ट ने यह निर्णय सम्यक विचारोपरान्त एक ऐसे मामले में दिया है, जिसमें एक व्यक्ति, जिसका जन्म हिन्दू परिवार में हुआ था और बाद में उसने हिन्दू धर्म छोड़ कर अपना नाम समीर अहमद रख लिया था। मुसलमान हो जाने के बाद उसने स्वयं को मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का सदस्य बताया। उसने अपने तहसीलदार से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की मांग की। तहसीलदार ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। तब वो हाईकोर्ट पहुंचा।

तमिलनाडु सरकार ने अपने आदेश में प्रावधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या डिनोटिफाइड समुदायों से आने वाले लोग यदि धर्मांतरण करते हैं और इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें भी पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। सरकार का तर्क था कि इससे मतांतरण करने वाले व्यक्तियों के भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी और स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण का आधार पंथ या मजहब नहीं होता। बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन होता है। कोर्ट ने साफ किया कि संवैधानिक श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को एक साथ मिला कर नई श्रेणी बनाना संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है।

मद्रास हाई कोर्ट ने ही 1951 के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि, "जब कोई हिन्दू इस्लाम अपनाता है तो वह सिर्फ मुसलमान बनता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा जाति के आधार पर नहीं होती। हिन्दू धर्म छोड़ते ही वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता।" आरक्षण का मसला भारत की संविधान सभा में भी आया था। मजहबी आधार पर ही देश का विभाजन हो चुका था। संविधान सभा बड़े उदास क्षणों में आरक्षण पर विचार कर रही थी। संविधान सभा ने सरदार पटेल की अगुवाई में अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने के लिए समिति बनाई थी। समिति ने अपनी सिफारिश में मजहबी आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया था।

सभा की अल्पसंख्यक अधिकारों, मूलाधिकारों संबंधी समिति के सभापति सरदार पटेल ने संविधान सभा में समिति की रिपोर्ट (25 मई, 1949) पेश की। लगातार दो दिन (25 व 26 मई, 1949) बहस हुई। जगत नारायण लाल ने कहा, "भारत एक लौकिक (सेकुलर) राज्य होगा। उसके बाद रक्षणों की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अनु. जातियों का प्रश्न है उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होने के कारण ही रक्षण दिया गया है।" ज्यादातर सदस्यों ने अनु. जाति के अस्थाई आरक्षण को सही बताया लेकिन 'आरक्षण' की मूल भावना को कोसा। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, "मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार के रक्षण स्वस्थ राजनीतिक विकास के प्रतिकूल हैं। उनसे एक प्रकार की हीन भावना प्रकट होती है। .....श्रीमान रक्षण ऐसा रक्षा उपाय है जिससे वह वस्तु जिसकी रक्षा की जाती है वह नष्ट हो जाती है। जहाँ तक अनु. जातियों का संबंध है, हमें कोई शिकायत नहीं है।" जेड.एच. लारी ने मुस्लिम आरक्षण की पैरवी करते हुए कहा, "आपको अनु. जाति के हितों की चिंता है। मुसलमानों के हितों की परवाह नहीं। अनु. जाति के स्थान रक्षण सिद्धांत के साथ क्या आप यह भी नहीं स्वीकार करते कि आरक्षण राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं है?" आरक्षण राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होता है। आरक्षण एक विशेष अस्थाई उपाय है। इसके नफा-नुकसान पर सम्यक विचार नहीं हुआ।

हालांकि संविधान निर्माताओं ने इसे सामाजिक पुनर्निर्माण का औजार बनाया। अनुसूचित जातियों/जनजातियों को जन्मना आधारित अस्थाई आरक्षण मिला। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग बनाने की व्यवस्था (अनु. 340) की गई। पं. नेहरू के समय (1953) पिछड़े वर्गों की खोज के लिए काका कालेलकर आयोग बना। आयोग के कई सदस्य जन्मना जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाने पर असहमत थे। आयोग ने राष्ट्रपति को लिखा, "समानता वाले समाज की ओर प्रगति में जाति प्रथा बाधा है। कुछ निश्चित जातियों को पिछड़ा मानने से यह हो सकता है कि हम जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव को सदा के लिए बनाए रखें।" नेहरू सरकार ने जाति के अलावा पिछड़ेपन का आधार जाँचने की कोई दीगर कसौटी खोजने की बात की। वीपी मण्डल के नेतृत्व में दूसरा आयोग बना। मण्डल आयोग की रिपोर्ट (1980) में 'जाति' को पिछड़ेपन का आधार बनाया गया। आयोग ने पिछड़ी जातियों की सूची भी बनाई। मण्डल ने गरीबी हटाने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आरक्षण से अलग रखने की आश्चर्यजनक बात कही, "गरीबी हटाने की राष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत अन्य पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने की समस्या आती है। पर यह बात अंशतः ही सही है। अन्य पिछड़ी जातियों का अभावग्रस्त होना एक अलग बड़ी राष्ट्रीय समस्या है।" (रिपोर्ट, पृ. 62) यानी देश के बाकी जनों की गरीबी अलग समस्या है। पिछड़ी जातियों की गरीबी भी विचारणीय है। लेकिन मजहबी आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है।

अन्ना हजारे ने किया अनशन का ऐलान

RTI नियमों में बदलाव वापस न लेने पर 5 जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर से अनशन कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) नियमों में किए गए बदलावों को तुरंत वापस नहीं लिया तो वह 5 जुलाई से अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हजारे ने अपने पत्र में कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12 जून को लागू किए गए 'महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026' RTI कानून की मूल भावना के खिलाफ हैं।

उनका कहना है कि इन नए नियमों से पारदर्शिता कमजोर होगी और आम नागरिकों के लिए जानकारी हासिल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अन्ना हजारे ने खास तौर पर RTI आवेदन फीस में बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने फीस बढ़ाने के पीछे कोई ठोस तर्क या वित्तीय विश्लेषण पेश नहीं किया है। हजारे ने स्पष्ट किया कि RTI कानून का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि जनता को सूचना का अधिकार देना है। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि फीस बढ़ाई जाती है, तो जानकारी देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, नए नियमों में RTI आवेदन के साथ पहचान पत्र देना अनिवार्य किए जाने पर भी हजारे ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि RTI एक्ट की धारा 6(2) के तहत आवेदक को अपनी निजी जानकारी या आवेदन का कारण बताने की कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान व्हिसलब्लोअर और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

हजारे ने 'एक विषय, एक आवेदन' जैसे नए नियम को भी अनावश्यक बताया। उनका कहना है कि इससे नागरिकों को बार-बार अलग-अलग आवेदन करने पड़ेंगे, जिससे प्रक्रिया जटिल और महंगी हो जाएगी। उन्होंने अपील खारिज करने, सुनवाई में कानूनी मदद पर रोक और आवेदक की मौत पर केस बंद करने जैसे प्रावधानों की भी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन नियमों को वापस नहीं लिया, तो वह 5 जुलाई से रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अनशन शुरू करेंगे।

जिस केमिकल ने वियतनाम के खेतों को झुलसाया, उसे भारत में इस्तेमाल की मंजूरी किसने दे दी?

वियतनाम वॉर अमेरिका के लिए 'वाटरलू' साबित हुआ था. यानी इस जंग में वियतनाम ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को नाको चने चबवा दिए थे. इसने अमेरिका की ग्लोबल पावर की छवि को भी खोखला साबित कर दिया था. अमेरिका ने इस युद्ध में जीत के लिए तमाम 'धतकर्म' किए थे. अमेरिकी लड़ाकू जहाजों ने वियतनाम के जंगलों और खेतों में लाखो लीटर 'एजेंट ऑरेंज' का छिड़काव किया था. एजेंट ऑरेन्ज एक तरह का केमिकल होता है, जिसका इस्तेमाल खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है.

अमेरिका ने वियतनाम के घने जंगलों और फसलों को बर्बाद करने के लिए इस खतनाक केमिकल को छिड़का था. जंगल और खेतों से वियतनाम के कम्युनिस्ट लड़ाकों को रसद मिलाता था. इस सप्लाई चेन को काटने के लिए अमेरिका की रणनीति में इस केमिकल ने एंट्री ली थी. इस जंग में तो एजेंट ऑरेन्ज से अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हुए लेकिन भारत के खेतों में 'ऑरेंज एजेंट' बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे दिया गया है. इस केमिकल का नाम है- 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसेटिक एसिड.

कहने को तो ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करता है. लेकिन असल में यह हमारी कृषि व्यवस्था की रीढ़ पर सीधा हमला है. फसलों में परागण (Pollination) करके लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाने वाली मधुमक्खियों का यह केमिकल बेरहमी से कत्ल कर रहा है. लेकिन मुनाफे की दौड़ में अंधी हो चुकी कंपनियां और सिस्टम के लोग भूल गए कि मधुमक्खियां खत्म हुईं तो पूरा ईकोसिस्टम तबाह हो जाएगा.

WHO की चेतावनी: इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ एग्रो केमिकल कंपनियों का अरबों का टर्नओवर और सस्ती खेती की दलील है. दूसरी तरफ मानव जीवन की सुरक्षा का सवाल. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर अनुसंधान संस्था को ग्रुप 2B (Possibly Carcinogenic) यानी इंसानों के लिए संभावित रूप से 'कैंसरकारी' केमिकल की श्रेणी में रखा है. दुनिया के विकसित देशों ने इसके खतरनाक एस्टर फॉर्मूलेशन पर भारी पाबंदी लगा रखी है.

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई

पूर्व डीजीएचएस समेत दो लोग गिरफ्तार, रडार पर वकील, IAS और सप्लायर, मंत्रालय तक पहुंची जांच

■ धर्मेन्द्र भदौरिया

नई दिल्ली। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में सामने आए करीब 650 करोड़ रुपये के दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले की जांच अब स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गई है।

विभाग में सक्रिय प्रभावशाली अधिवक्ता, आईएएस अधिकारी और सप्लायर रंगीला ब्रदर्स की तिकड़ी घोटाले को लेकर जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि प्रभावशाली अधिवक्ता और विभागीय अधिकारियों से नजदीकियों का लाभ उठा रंगीला ब्रदर्स ने नियुक्तियों व खरीद प्रक्रिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए मनमाफिक पोस्टिंग, टेंडर आवंटन के साथ डीजीएचएस की नियुक्ति कराई। इसके बाद पहले बिना आवश्यकता के सामान की जरूरत पैदा की गई फिर वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत पर उसकी सप्लाई कर सरकारी धन की लूट की गई।

16 लाख से अधिक चादरों की खरीदारी की गई

गर्मी बढ़ने पर दिल्ली को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए कूलिंग जोन के लिए ढाई रुपये के ओआरएस पैकेट की 15 रुपये में की गई 50 लाख पैकेज की आपूर्ति और सप्ताह के अलग-अलग दिनों में मरीजों को 'फील गुड' कराने को अलग-अलग रंगों की सरकारी अस्पतालों के 15 हजार 600 बिस्तरों के लिए 450 रुपये के भाव से 16 लाख से अधिक चादरों की खरीदारी की गई। वहीं, जबकि इन्हीं चादरों की इसी सप्लायर ने एम्स और दूसरे अस्पतालों में 150 रुपये में आपूर्ति की है। इस मामले को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर चिकित्सा सामग्री आपूर्ति से जुड़े रंगीला ब्रदर्स, उसके प्रमुख चेहरों में शामिल राजीव रंगीला, एक प्रभावशाली अधिवक्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्व आईएएस अधिकारी तपस्या राघव व अन्य आईएएस अधिकारियों की भूमिका आ गई है।

सूत्र बताते हैं कि एक मंत्री और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की निकटता का लाभ उठाकर सप्लायर राजीव रंगीला ने विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती कराई। उसके बाद इन लोगों की मदद से 650 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। अब यह पता लगाया जा रहा है कि बाद में इन्हीं अधिकारियों के कार्यकाल में विवादित खरीद और टेंडर प्रक्रियाओं को मंजूरी कैसे मिली।

15 वरिष्ठों की अनदेखी कर हुई थी डा. वत्सला की नियुक्ति

जांच एजेंसियां पूर्व डीजीएचएस डा. वंदना बग्गा, डा. रति मक्कड़, डा. राजेश कुमार तथा डा. वत्सला अग्रवाल के कार्यकाल से जुड़े निर्णयों की भी समीक्षा कर रही हैं। वरिष्ठता क्रम को लेकर हुए कुछ प्रशासनिक फैसले भी जांच के दायरे में हैं। पता लगाया जा रहा है कि लगभग 15 वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड कर डा. वत्सला अग्रवाल को क्यों और किसके कहने पर डीजीएचएस नियुक्त किया गया। क्योंकि उनके आने के बाद ही खरीद प्रक्रिया, टेंडर आवंटन और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई। इस मामले में तत्कालीन विशेष सचिव (स्वास्थ्य) तपस्या राघव (आइएएस) सहित उनके समय में मंत्रालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की भी पड़ताल हो रही है।

नीरज चोपड़ा को भी एसीबी ने किया गिरफ्तार

एसीबी ने इस मामले में डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का मानना है कि दोनों की भूमिका कथित वित्तीय अनियमितताओं में महत्वपूर्ण हो सकती है।एसीबी इससे पहले सीपीए के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार कर चुकी है। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

सरकार ने 7 कर्मियों को किया निलंबित

उधर, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के विभिन्न स्टोर्स में जांच के अनियमितताएं मिलने पर पांच फार्मासिस्टों और दो अधिकारियों को तत्काल से प्रभाव निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन में लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वाले अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

वेंडरों से एसीबी कर रही पूछताछ

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े वेंडरों समेत कई लोगों को पूछताछ कर रही है। सामने आ रहे तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों से अलग-अलग स्तर पर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी टेंडर मंजूरी, दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति, भुगतान, फाइलों के अनुमोदन और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने की पुष्टि होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर सोमवार को घेवरा मोड़ स्थित स्वाभिमान स्थल पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। 'दिल्ली देहात के शेर' कहे जाने वाले वर्मा जी को श्रद्धांजलि देने हजारों लोग पहुंचे।

मंत्री, सांसद, विधायक रहे मौजूद

सभा में दिल्ली सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाग लिया। बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति ने दिखाया कि साहिब सिंह वर्मा आज भी दिल्लीवासियों के दिलों में बसे हैं।

दूरदर्शी प्रशासक के रूप में याद किया

सभा में मौजूद नेताओं ने साहिब सिंह वर्मा को दूरदर्शी प्रशासक, शिक्षाविद् और जननेता बताया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा, आधारभूत संरचना और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में उनका योगदान आज भी दिल्ली के विकास को दिशा दे रहा है। मुंडका के किसान परिवार में जन्मे साहिब सिंह वर्मा सार्वजनिक जीवन के शीर्ष पदों तक पहुंचे, लेकिन ग्रामीण दिल्ली की संस्कृति और मूल्यों से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा।

'सादगी और ईमानदारी की मिसाल'

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और निस्वार्थ जनसेवा का उदाहरण रहा। उन्होंने हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि वर्मा जी मानते थे कि राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ समाज सेवा का पवित्र दायित्व है। उनके हर निर्णय के केंद्र में आम नागरिकों का हित होता था। हम उनके समावेशी और जन-केंद्रित सुशासन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दिल्ली के आजादपुर इलाके से दो बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां के आजादपुर इलाके से गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपित ऐसा है जिसे पिछले वर्ष गिरफ्तार कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वह दोबारा भारत में घुस आया। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप वाले दो स्मार्टफोन, बांग्लादेशी पहचान पत्र और एक मिर्ची स्प्रे बरामद किया है। उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहम्मद रुहुल अमीन उर्फ तुली दास और एमडी जीबोन मियां उर्फ लिली के रूप में हुई है। दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और भारत में रहने के लिए उनके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिले।

उन्होंने बताया कि 25 जून की सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के एनएस मंडी, आजादपुर इलाके में दो बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इस आधार पर इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि रुहुल अमीन को जून 2025 में भी उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने गिरफ्तार किया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन वह दोबारा अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर महेंद्र पार्क इलाके में रहने लगा। पुलिस ने उसे फिर से ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि रात के समय वे दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में ट्रांसजेंडर का भेष बनाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। वे कथित तौर पर ग्राहकों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल भी करते थे। रुहुल अमीन के बैग से एक मिर्ची स्प्रे बरामद किया गया है। दूसरा आरोपित जीबोन मियां इलाके में रसोइए का काम करता था और दोनों साथ रह रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों के कब्जे से प्रतिबंधित आईएमओ एप इंस्टॉल दो स्मार्टफोन और बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश कर उनके निर्वासन (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि दोनों किन लोगों के संपर्क में थे, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने में किसने उनकी मदद की और क्या इस नेटवर्क से अन्य लोग भी जुड़े हैं। मामले की जांच जारी है।

लंबे समय तक युवा बने रहने के लिए बेहतरीन टिप्स

बढ़ती उम्र में अपने शरीर और मन को युवा, स्वस्थ और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखना कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और बुढ़ापे को मानसिक रूप से कैसे देखते हैं। यदि आप लगातार खुद को प्रेरित करते रहें, खुद को चुनौती देते रहें और अपना ख्याल रखते रहें, तो आप किसी भी उम्र में एक परिपूर्ण और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन बात बारीकियों पर भी आती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और बेहतर दिखने के लिए आप जिन रणनीतियों, युक्तियों और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां कुछ बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं।

संतुलित आहार

जवानी भरी रंगत और स्वस्थ कोशिकाओं व अंगों को बनाए रखने के लिए सही आहार बेहद ज़रूरी है। विटामिन, खनिज, एंजाइम, अमीनो एसिड... ये सभी शरीर के अनगिनत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ज़िम्मेदार हैं। इनकी कमी से धीरे-धीरे नुकसान बढ़ता जाता है, जो बुढ़ापे में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ और संतुलित आहार लें, इससे आप इन नकारात्मक प्रभावों से बच सकेंगे। किसी पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें, यह आपके द्वारा किए जाने वाले सर्वोत्तम निवेशों में से एक होगा।

बेरी स्मूदी का आनंद लें

यदि आप ऐसा भोजन चाहते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो और उम्र बढ़ने के प्रभावों को धीमा करने में सहायक हो, तो ब्लूबेरी पर विचार करें। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट के बेहतरीन स्रोतों में से एक हैं और स्मूदी एक सुविधाजनक और स्वादिष्ट तरीका है जिससे आप आसानी से इन्हें अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

मछली, मांस और सोयाबीन खाएं

अमीनो एसिड न केवल आपके सामान्य स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन स्रोतों का सेवन बढ़ाने से आपको सिस्टीन भी मिलेगा – जो ग्लूटाथियोन का एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है – जो सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सिडेंट में से एक है और जिसे अक्सर 'मास्टर' एंटीऑक्सिडेंट माना जाता है।

हड्डी का सूपः अस्थि शोरबा पशुओं की हड्डियों को उबालकर बनाया जाता है और फिर उस तरल को सूप के रूप में पिया जाता है। यह संयोजी ऊतकों और हड्डियों को मजबूत बनाने में अत्यंत प्रभावी है और बढ़ती उम्र में हड्डियों की मजबूती बढ़ाने और टूटने से बचाने में सहायक हो सकता है।

कैफीन का सेवन करें

कैफीन उम्र से संबंधित तंत्रिका संबंधी गिरावट की संभावना को कम करने में मदद करता है और न्यूरॉन्स को ऑक्सीकरण से बचाता है।

ओमेगा 3 फैटी एसिड

मस्तिष्क को संज्ञानात्मक गिरावट से बचाने, कोशिकाओं को नुकसान से बचाने और सूजन को कम करने के लिए, ओमेगा 3 कोशिकाओं की झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाकर और सूजन पैदा करने वाले ओमेगा 6 की अत्यधिक मात्रा को कम करके काम करता है।

रेस्वेराट्रोल

रेस्वेराट्रोल लाल अंगूर और लाल वाइन में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में अत्यधिक प्रभावी है, जिसका अर्थ है ऑक्सीकरण में कमी।

ल्यूटिन

एक अन्य पदार्थ जो माइटोकॉन्ड्रियल कार्यप्रणाली को बेहतर बना सकता है, वह है ल्यूटिन। उम्र बढ़ने के साथ-साथ ल्यूटिन आंखों को मैकुलर डिजनरेशन से भी बचाता है, जिससे यह एंटी-एजिंग सप्लीमेंट के रूप में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

जेडएमए

ZMA जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 का मिश्रण है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने और नींद में सुधार करने के लिए यह एक बेहद शक्तिशाली संयोजन है।

विटामिन डी

प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है और हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह सर्दी-जुकाम होने की संभावना को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है। वास्तव में, कुछ मामलों में यह टीकों से भी अधिक प्रभावी हो सकता है। बढ़ती उम्र में सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विटामिन का सेवन करें। यह कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, जिससे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है।

हल्दी

हल्दी के शरीर के लिए कई शक्तिशाली लाभ हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प लाभों में से एक है मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को बढ़ाने की इसकी क्षमता। बढ़ती उम्र के मस्तिष्क के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहज बुद्धि और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

मैग्नीशियम थ्रियोनेट

मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को बेहतर बनाने के लिए एक और शक्तिशाली सप्लीमेंट मैग्नीशियम थ्रियोनेट है। इस यौगिक की संरचना के कारण, यह आसानी से अवशोषित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मृति और सीखने की क्षमताओं को बेहतर बनाता है।

हाईऐल्युरोनिक एसिड

अपनी त्वचा को जवां बनाए रखने के लिए, हाइलूरोनिक एसिड जैसे ह्यूमेक्टेंट युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करें।

विटामिन ई

विटामिन ई एक और महत्वपूर्ण पदार्थ है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने, त्वचा को हाइड्रेट करने और उम्र बढ़ने के साथ झुर्रियों को आने से रोकने में मदद करता है। बेशक, आप इन सभी पोषक तत्वों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आपको स्वस्थ, संतुलित और पौष्टिक आहार बनाए रखते हुए अपने लिए उपयुक्त पोषक तत्वों को चुनना और उनका उपयोग करना होगा।

सनस्क्रीन

क्या आप अपने ऑफिस में खिड़की के पास बैठते हैं? खिड़की सूरज की UVB किरणों को तो रोकती है, लेकिन UVA किरणों को नहीं। इसका मतलब है कि ये किरणें त्वचा की कोशिकाओं में गहराई तक जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, यही वजह है कि हमारे चेहरे के एक तरफ अक्सर ज्यादा झाइयां होती हैं। जी हां, इसलिए घर के अंदर भी सनस्क्रीन जरूर लगाएं!

अपने पानी को आयनित करें

पानी को आयनित करने वाला फिल्टर आपके पानी में मौजूद फ्री रेडिकल की गतिविधि को कम करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार आपको युवा और लंबे समय तक स्वस्थ दिखने में मदद कर सकता है, साथ ही कैंसर की शुरुआत से भी बचा सकता है।

बढ़ती उम्र के साथ त्वचा को जवां और नमीयुक्त बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया गया है, ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम चुनें जिसमें थोड़ी मात्रा में सनब्लॉक भी हो, ताकि समय के साथ कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अपने हाथों को भी मॉइस्चराइज करें! अक्सर हमारे हाथ ही हमारी असली उम्र बता देते हैं, भले ही हम देखने में जवान लगें।

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा

मुंबई। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) की परीक्षा होने वाली है। इससे पहले इसका पेपर लीक हो गया है। इस वजह से एग्जाम रद्द कर दी गई है। इस मामले में अब राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार ने देश की शिक्षा और परीक्षा को वसूली का सिस्टम बना दिया है। देश का हर युवा असुरक्षित राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, एक और पेपर लीक। एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का TET, देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है। वहीं, कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया जारी की है। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भाजपा सरकार को घेरने का काम किया है। सरकार पर आरोप लगाया, एक और पेपर लीक. महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हो गया है। कल ये परीक्षा होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं, जो लीक नहीं होता। ये सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है। एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक और महाराष्ट्र पेपर लीक का हवाला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस पर निशाना साधा है।

कजाक कुरेस चैंपियनशिप में दिल्ली ने जीते 8 पदक

नई दिल्ली। हरियाणा के पानीपत में आयोजित 5वीं कजाक कुरेस चैंपियनशिप में दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल आठ पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में दिल्ली के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में दमदार खेल दिखाकर एक स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदक जीते। पुरुष वर्ग में 90 किलोग्राम भार वर्ग में अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 66 किलोग्राम में कुणाल वत्स और 82 किलोग्राम में हितेन ने रजत पदक जीता। वहीं 60 किलोग्राम में तरुण तथा 74 किलोग्राम में लवलीन ने कांस्य पदक हासिल कर दिल्ली की पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिला वर्ग में 60 किलोग्राम भार वर्ग में नेहा ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतकर दिल्ली का नाम रोशन किया। 48 किलोग्राम में सीमा और 52 किलोग्राम में शगुन शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान दिल्ली के खिलाड़ियों ने तकनीकी कौशल, अनुशासन और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर कोचों और टीम प्रबंधन ने उन्हें बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।

पार्टनर को खुश करने के कुछ तरीके जाने

प्यार का रिश्ता कहने को बड़ा ही अनमोल और प्यार की मिठास से भरा होता है, जिसमें दोनों पार्टनर एक-दूसरे की बातों में खोए रहते हैं, एक-दूसरे के साथ अपने आने वाले भविष्य को लेकर कई सपने सजाते हैं आदि। लेकिन इस प्यार के रिश्ते में जितनी खुशियां होती हैं, उतनी ही टकरार भी इसी रिश्ते में देखी जाती है। इस रिश्ते की शुरुआत के समय दोनों पार्टनर काफी खुश होते हैं और एक लंबा समय साथ में बिताकर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधते हैं। लेकिन शादी से पहले जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उसमें कई बार रूठने-मनाने जैसी चीजें चलती रहती हैं। शायद इन्हीं चीजों के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। वहीं, कई बार लोग अपने पार्टनर को खुश तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं? अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो चलिए हम आपके पार्टनर को खुश करने के कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं।

तारीफ करना

तारीफ ऐसी चीज है, जो आपके पार्टनर को मिनटों में खुश कर सकती है। जब भी आपके पार्टनर कोई ड्रेस पहने, किसी पार्टी या किसी खास मौकों के लिए तैयार हों या फिर रोजाना भी आप उनको देखकर उनकी तारीफ कर सकते हैं और यकीन मानिए ऐसा करने से आपके पार्टनर काफी खुश होंगे। ये तरीका महिला पार्टनर पर ज्यादा काम करता है।

अपनापन जताना

हर कोई चाहता है कि आप जिसके साथ हैं, वो आप पर अपनापन जताए। आपकी सुरक्षा करे, आपकी चिंता करे, आपके बारे में सोचे और आपकी हर काम में मदद करे आदि। जब आप ये सब करते हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि हां आप उनकी चिंता करते हैं यानी आप अपनापन जता रहे हैं और किसी भी पार्टनर को खुश करने के लिए ये बेहतर तरीका हो सकता है।

उपहार देना

उपहार भला किसे पसंद नहीं होते? हर कोई चाहता है कि उनका पार्टनर उन्हें उपहार दें। आप जब मिलने जा रहे हैं, तो कभी-कभी एक गुलाब का फूल ले जा सकते हैं, कभी उनकी पसंद का कोई उपहार उन्हें दे सकते हैं या फिर सरप्राइज गिफ्ट भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो आपके पार्टनर को खुश रखने में मदद कर सकता है।

सच बोलना

सच ऐसी चीज है, जो हर किसी को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है और ये वही चीज है जो बता सकती है कि हां आप कितने सच्चे हैं। इसके साथ ही आपका सच किसी के चेहरे पर खुशी तक ला सकता है। जैसे- आपके पार्टनर के चेहरे पर। अगर आप अपने पार्टनर से सच बोलेंगे, तो वो आपसे काफी खुश होंगे।

गर्मी में पसीने की बदबू से हैं परेशान? आजमाएं ये नुस्खे

गर्मी और उमस के मौसम में पसीना आना एक सामान्य बात है, लेकिन जब पसीने की बदबू आपकी पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास पर असर डालने लगे, तो यह परेशानी का कारण बन जाती है। कई लोग महंगे परफ्यूम और डियोड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद भी शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसका कारण केवल पसीना नहीं, बल्कि त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, जो पसीने के संपर्क में आकर बदबू पैदा करते हैं।ढअगर आप भी बार-बार परफ्यूम लगाने के बावजूद फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, तो सिर्फ परफ्यूम पर निर्भर रहने के बजाय नहाने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजें नहाने के पानी में मिलाकर इस्तेमाल की जाएं, तो शरीर को ताजगी का एहसास मिल सकता है और बदबू कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये घरेलू उपाय व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं और इनके परिणाम व्यक्ति-व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। यदि अत्यधिक पसीना या तेज दुर्गंध लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है। आइए जानते हैं ऐसी 3 घरेलू चीजों के बारे में जिन्हें नहाने के पानी में मिलाकर आप खुद को ज्यादा फ्रेश महसूस कर सकते हैं।

नींबू का रस

नींबू को प्राकृतिक रूप से ताजगी देने वाला माना जाता है।

कई लोग नहाने के पानी में थोड़ा नींबू रस मिलाकर स्नान करना पसंद करते हैं।

इससे त्वचा पर ताजगी महसूस हो सकती है।

शरीर से आने वाली हल्की बदबू को कम करने में मदद मिल सकती है।

कैसे इस्तेमाल करें?

एक बाल्टी पानी में 1 से 2 नींबू का रस मिलाएं और उससे स्नान करें।

गुलाब जल

गुलाब जल त्वचा को ठंडक और ताजगी देने के लिए काफी लोकप्रिय है।

इसकी हल्की खुशबू शरीर को लंबे समय तक फ्रेश महसूस करा सकती है।

गर्मियों में नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाना कई लोगों का पसंदीदा घरेलू उपाय माना जाता है।

कैसे इस्तेमाल करें?

एक बाल्टी पानी में 2 से 3 चम्मच गुलाब जल मिलाएं और नहाने के बाद शरीर को प्राकृतिक खुशबू का एहसास दें।

फिटकरी का पानी

फिटकरी का उपयोग लंबे समय से व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए किया जाता रहा है।

कुछ लोग इसे शरीर की दुर्गंध कम करने के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

फिटकरी को पानी में घोलकर नहाने से त्वचा पर ताजगी महसूस हो सकती है।

कैसे इस्तेमाल करें?

थोड़ी सी फिटकरी को पानी में घोलें और सामान्य स्नान की तरह उपयोग करें।

मनोरंजन

राजकुमार राव का पहला इम्प्रेशन दिल-दिमाग हिला देने वाला!

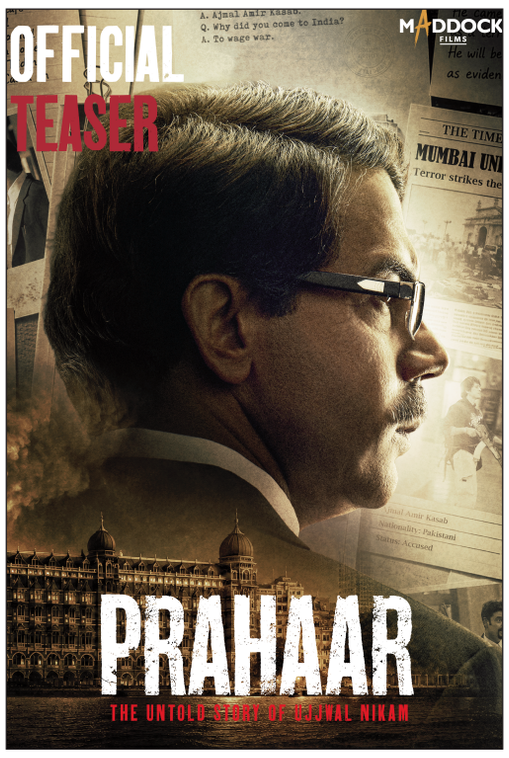

प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी का टीज़र आखिरकार आउट हो चुका है-और आते ही ऐसा झटका देता है कि नजर हटाना मुश्किल। ये फिल्म भारत के सबसे चर्चित स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स में से एक, उज्ज्वल निकम की ज़िंदगी और करियर से इंस्पायर्ड है, और टीज़र पहली ही झलक में इसकी पावरफुल टोन सेट कर देता है।

हर किरदार में पूरी तरह घुस जाने वाले राजकुमार राव इस बार फिर अपनी एक्टिंग की गिरगिट-टाइप रेंज दिखाते नजर आ रहे हैं। वो ऐसे इंसान का रोल निभा रहे हैं जो देश की कई बड़ी कानूनी लड़ाइयों का चेहरा रहा है। उज्ज्वल निकम का करियर कई हाई-प्रोफाइल केस से भरा पड़ा है, लेकिन टीज़र साफ इशारा देता है कि फिल्म का फोकस उनकी जिंदगी के सबसे अहम चैप्टर पर रहेगा-26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद अजमल कसाब के ट्रायल पर। इसी कहानी के जरिए प्रहार उस लीगल बैटल को सामने लाने वाली है जिसने पूरे देश को एक साथ स्क्रीन से चिपका दिया था।

टीज़र एक इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा की झलक देता है -जहां हर सीन में टेंशन, दमदार बहस और इमोशनल पंच है। और इस पूरे खेल को राजकुमार राव बड़ी मजबूती और कंट्रोल के साथ लीड करते नजर आते हैं। टीज़र की सबसे खास बात है राजकुमार का ऑथेंटिसिटी वाला कमिटमेंट। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज, और खासकर मराठी पर पकड़- सब कुछ इतना डिटेल में काम किया गया है कि किरदार स्क्रीन पर पूरी तरह असली लगता है। ऊपर से टीज़र के डायलॉग्स भी ऐसे हैं जो सीधे सीने में लगते हैं -मतलब थिएटर वाला एक्सपीरियंस फुल पावर में आने वाला है।

पाताल लोक और थ्री ऑफ अस जैसे सराहे गए प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर अविनाश अरुण इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और यहां भी उनका वही ग्राउंडेड और शार्प टच नजर आता है -जो कहानी को सिर्फ थ्रिलिंग ही नहीं, इमोशनली भी गहरा बनाता है। राजकुमार राव के साथ फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दमदार कहानी, तगड़ी परफॉर्मेंस और इमोशन से भरी नैरेटिव के साथ प्रहार-द उज्ज्वल निकम स्टोरी 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

नीरू शर्मा ने लेखन और निर्देशन में बनाई नई पहचान

भारतीय पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक समय बिताने और देश के प्रमुख समाचार चैनलों में काम करने के बाद नीरू शर्मा ने अब लेखक और फिल्म निर्देशक के रूप में अपनी नई पहचान बनानी शुरू की है। मनोरंजन जगत को वर्षों तक करीब से देखने और समझने के बाद उन्होंने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को फिल्म निर्माण की दिशा में मोड़ा है। सुभाष घई के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल से निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली नीरू शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता ने उन्हें समाज, लोगों और कहानियों को गहराई से समझने का अवसर दिया, जबकि फिल्म निर्माण ने उन अनुभवों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का मंच प्रदान किया। वह व्हिसलिंग वुड्स की पूर्व छात्रा (Alumna) भी हैं।

उनकी पहली फिल्म 'बांद्रा बॉय' एक थ्रिलर है, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि किस प्रकार मीडिया नैरेटिव, सामाजिक पूर्वाग्रह और जनधारणाएं कई बार वास्तविक तथ्यों के सामने आने से पहले ही लोगों की राय को प्रभावित कर देती हैं। सेलिब्रिटी संस्कृति और सार्वजनिक जांच-पड़ताल की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म धारणा और वास्तविकता के बीच की महीन रेखा को उजागर करती है।

फिल्म में अहवान कुमार मुख्य भूमिका में हैं, जबकि गुजराती और मराठी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता धर्मेंद्र गोहिल पिता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कलाकारों की टीम में व्हिसलिंग

वुड्स के पूर्व छात्र लोचन बरसागड़े, रंगमंच अभिनेता यश पेडणेकर, टेलीविजन अभिनेता पवन तिवारी और श्याम थोंबरे भी शामिल हैं।

फिल्म जगत के जानकारों का मानना है कि पत्रकारिता से फिल्म निर्माण की ओर कदम बढ़ाने वाले लोग अपेक्षाकृत कम होते हैं। ऐसे में नीरू शर्मा की यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन उद्योग को वर्षों तक करीब से देखने का अनुभव और फिल्म निर्माण की औपचारिक शिक्षा, दोनों का समावेश है।

फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 'बांद्रा बॉय' को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों की प्रतियोगिता श्रेणी (Competition Category) में भेजा गया है। फिल्म का विषय आज के समय में और भी प्रासंगिक माना जा रहा है, जब लोगों की राय अक्सर सुर्खियों, अटकलों और वायरल चर्चाओं के आधार पर बन जाती है। नीरू शर्मा का कहना है कि पत्रकारिता के दौरान उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे, जहां वास्तविकता से पहले धारणाएं स्थापित हो जाती थीं। यही अनुभव उन्हें ऐसी कहानियां लिखने और बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करें।

निर्देशन के साथ-साथ नीरू शर्मा पटकथा लेखन पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। उनकी कहानियां समकालीन विषयों, मानवीय भावनाओं और सामाजिक सरोकारों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। उद्योग से जुड़े लोग उनकी रचनात्मक दृष्टि को अवलोकन, संवेदनशीलता और यथार्थपरक कहानी कहने की क्षमता से जोड़कर देखते हैं। 'बांद्रा बॉय' के साथ नीरू शर्मा ने अपने पेशेवर जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। वर्षों तक दूसरों की कहानियां रिपोर्ट करने के बाद अब वह अपनी कहानियां स्वयं गढ़ रही हैं। फिल्म समारोहों की यात्रा के साथ उनका यह कदम एक ऐसी फिल्मकार के रूप में उभरने का संकेत देता है, जिसकी दृष्टि पत्रकारिता के अनुभव और रचनात्मक अभिव्यक्ति दोनों से समृद्ध है।

रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं फिल्म 'बेबी डू डाई डू'

एक्टर रचित सिंह अपनी आने वाली फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें वो सिद्धू का किरदार निभाएंगे नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज से पहले रचित ने डायरेक्टर नचिकेत सामंत के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उनके शांत और सुकून भरे अंदाज ने सेट पर बिल्कुल नेचुरल माहौल बना दिया। रचित ने बताया कि नचिकेत का रिलैक्स्ड वर्किंग स्टाइल एक्टर्स को पूरी तरह अपने किरदार में घुसने का मौका देता है, जिससे पूरी क्रिएटिव प्रोसेस काफी सहज और सहज लगती है।

डायरेक्टर के साथ काम करने पर रचित बोले, "नाची के साथ काम करना काफी रिलैक्स्ड था क्योंकि वो बहुत चिल और शांत हैं। सेट पर चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैनिक नहीं करते, और उनकी यही एनर्जी एक्टर को ग्राउंडेड रहने और उस पल में प्रेजेंट रहने में मदद करती है। वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन एक-दो शब्द या छोटे पॉइंटर्स देकर सीन को समझते हैं, उसके स्टेक्स बढ़ाने और कैरेक्टर को बेहतर कैचिंग में मदद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "उनके लिए ज़्यादा तैयारी (Preparation) नहीं रूह, बल्कि वो पल में जीने, सुनने, डायरेक्शन लेने और सीन को नेचुरल तरीकों से होने देने में विश्वास रखते हैं। नचिकेत के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा।"

'बेबी डू डाई डू' में रचित सिद्धू का किरदार निभा रहे हैं, जो एक म्यूजिशियन और म्यूजिक टीचर है—दिल से अच्छा इंसान, जो अपने चाहने वालों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। यह किरदार उनके पिछले इंटेंस और डार्क कैरेक्टर वीरेन (फिल्म 'थम्मा') से बिल्कुल अलग है। सिद्धू के ज़रिए रचित इस बार अपने क्राफ्ट का एक सॉफ्ट और दिल छू लेने वाला साइड दिखाने वाले हैं। 'बेबी डू डाई डू' 3 जुलाई को रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

मुनव्वर फारुकी ने मनाया जश्न

एक साल पहले, फर्स्ट कॉपी ने दर्शकों को मुनव्वर फारुकी का एक बिल्कुल नया अवतार दिखाया था। 20 जून 2025 को रिलीज़ हुई इस क्राइम थ्रिलर ने कॉमेडियन और शायर मुनव्वर के एक्टिंग करियर की आधिकारिक शुरुआत की और देखते ही देखते ये शो चर्चा का हॉट टॉपिक बन गया। 90 के दशक की मुंबई के नॉस्टैल्जिक माहौल में सेट इस शो ने वीएचएस और वीडियो पाइरेसी की उस दुनिया को दिखाया, जो बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे चुपचाप फल-फूल रही थी। मुनव्वर ने इसमें आरिफ का किरदार निभाया — एक तेज़, महत्वाकांक्षी लड़का जो अपनी किस्मत बदलने की जिद में लगा है। वॉकमैन बेचने वाले एक स्ट्रीट सेलर से शुरू होकर, आरिफ का सफर उसे ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां चालाकी, पावर और सर्वाइवल ही असली गेम बन जाते हैं।

शो की पहली सालगिरह पर मुनव्वर ने कहा, "यकीन ही नहीं होता कि फर्स्ट कॉपी को रिलीज़ हुए एक साल हो गया है। आरिफ का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद खास था क्योंकि ये मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था। रिलीज़ से पहले मैं काफी नर्वस था, लेकिन दर्शकों के प्यार और सपोर्ट ने सब कुछ वर्थ इट बना दिया। दोनों सीज़न को जो रिस्पॉन्स मिला, वो जबरदस्त था और मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। ये शो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा।" इस शो ने दर्शकों के दिलों को छुआ और कमर्शियल तौर पर भी शानदार सफलता हासिल की, जिसके चलते उसी साल इसका दूसरा सीज़न भी आ गया। एक साल पूरा होने के साथ ही फर्स्ट कॉपी मुनव्वर के करियर का एक अहम पड़ाव बन चुका है- जिसने उन्हें सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि एक दमदार एक्टर के रूप में भी स्थापित कर दिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो मुनव्वर अब महेश मांजरेकर के अपकमिंग प्रोजेक्ट अंगाडिया की तैयारी में जुटे हैं।

नए अंदाज़ में लौटा, नीति मोहन और यासिर देसाई का 'तेरी उम्मीद आज भी'

इस वल्र्ड म्यूज़िक डे पर म्यूज़िक लवर्स के लिए एक दिल छू लेने वाला सरप्राइज़ तैयार है, क्योंकि तेरी उम्मीद आज रिलीज़ हो रहा है, एक ऐसा गाना जो अपने टाइमलेस इमोशन्स को एक फ्रेश साउंड के साथ वापस लेकर आ रहा है। यासिर देसाई और श्रुति शर्मा पर फिल्माया गया यह गाना प्यार, इंतज़ार और उन यादों की कहानी कहता है जो वक्त के साथ कभी फीकी नहीं पड़तीं। अपने नॉस्टैल्जिक दिल और मॉडर्न टच के साथ, यह ट्रैक पुराने रोमांटिक्स और आज की जनरेशन, दोनों के दिलों को छूने का वादा करता है। जावेद मोहसिन की सुपरहिट जोड़ी ने इस गाने को फिर से क्रिएट किया है, जहां क्लासिक इमोशन को मॉडर्न म्यूज़िक के साथ खूबसूरती से मिलाया गया है। यह सिर्फ रीक्रिएशन नहीं है, बल्कि एक नई सोच के साथ बनाया गया फ्रेश म्यूज़िकल पीस है, जिसमें पुराने गाने की रूह बरकरार है, लेकिन साउंड पूरी तरह आज की जनरेशन के लिए है। मकसद साफ है, मिलेनियल्स को नॉस्टैल्जिया देना और Gen Z को एक ऐसा गाना देना जिसे वो अपना कह सकें। नीति मोहन और यासिर देसाई की दिल छू लेने वाली आवाज़ें इस गाने में हर एहसास को और गहराई देती हैं। इसका म्यूज़िक वीडियो अब इश्तार म्यूज़िक पर उपलब्ध है, जो गाने की इमोशनल जर्नी को विज़ुअली और भी खास बना देता है। गाने के बारे में बात करते हुए यासिर देसाई ने कहा, "यह गाना मेरे दिल के बहुत करीब है।

भांग, चंदन और रजत आभूषणों से बाबा महाकाल का किया गया श्रृंगार

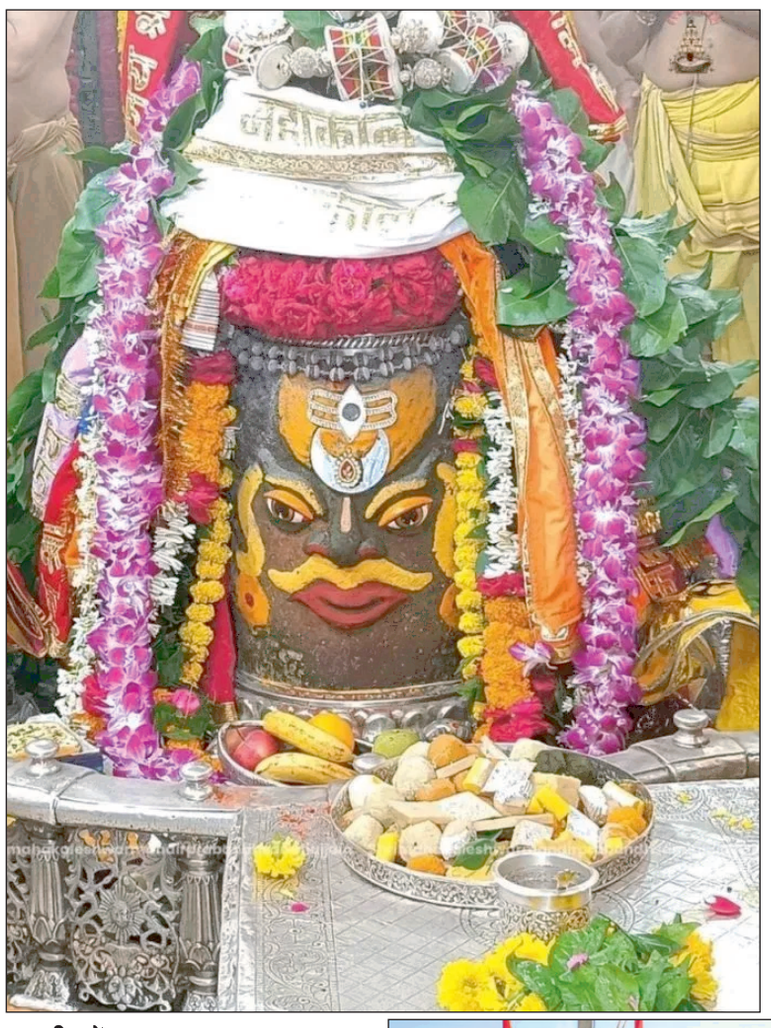

उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भक्तों ने देर रात से ही कतारबद्ध होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। सोमवार तड़के भगवान वीरभद्र की आज्ञा लेने के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ बाबा महाकाल के कपाट खोले गए। दिव्य श्रृंगार और भस्म आरती के बाद जैसे ही श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हुए, पूरा मंदिर परिसर ₹जय श्री महाकाल₹ के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर परिसर घंटियों, शंखध्वनि और मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो उठा। महाकाल मंदिर के पट खुलने के साथ ही मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल को हरि ओम का जल अर्पित किया गया। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन और रजत आभूषणों से दिव्य श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर के पुजारी ने महाआरती संपन्न कराई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। अपने आराध्य देव के दर्शन पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीती रात से ही बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहे। जानकारी के मुताबिक, पहले महाकाल को शमशान की राख अर्पित की जाती थी, लेकिन अब विशेष रूप से कपिला गाय के गोबर और औषधीय जड़ी-बूटियों से तैयार भस्म का उपयोग होता है। भस्म आरती के दौरान पुरुषों के लिए पारंपरिक धोती-सोला और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। बाबा महाकाल की आरती देश-विदेश में मशहूर है, जिसे देखने के लिए जनसामान्य से लेकर बड़ी हस्तियां भी आती हैं। इस दौरान मंदिर के आसपास व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है।

पुरी में भगवान जगन्नाथ की सालाना 'स्नान यात्रा' के लिए तैयारी पूरी

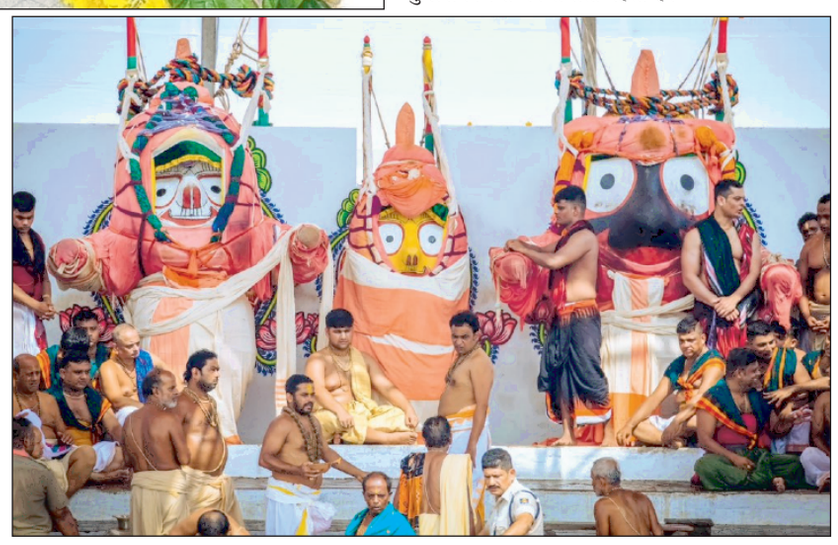

पुरी। पवित्र शहर पुरी सोमवार को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की 'स्नान यात्रा' (यानी स्नान उत्सव) के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने रथयात्रा से पहले होने वाले इस कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 'स्नान यात्रा' का दिन भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन भी माना जाता है। देशभर से श्रद्धालु देवताओं की पारंपरिक 'पहांडी' (शोभा यात्रा) देखने के लिए इस तीर्थ शहर में पहुंचने लगे हैं, यह शोभा यात्रा सुबह पांच बजे से सात बजे के बीच निकाली जाएगी।

पाना चाहते हैं जीवन में सुख और शांति, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

जीवन जीने की अनेक विधियां हैं, अनेक मार्ग हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुखमय जीवन कैसे जिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, क्योंकि सुख से ही जीवन में प्रसन्नता आती है। इसी प्रसन्नता की खोज के लिए मनुष्य अनेक उपाय करता है। इसी सुख की खोज के लिए मनुष्य अनेक उपाय करता है, इसी सुख की खोज के लिए वह व्यापार करता है, राजनीति में जाता है या नौकरी करता है। इसी सुख की खोज में वह भटक भी जाता है और ऐसा भटकता है कि जिस जीवन को सुखी बनाने के लिए वह बहुत कुछ करना चाहता है, उसी प्रयास में उसका जीवन कहीं गुम हो जाता है। मनुष्य के जीवन के दुर्भाग्य की कहानी यहीं से शुरू होती है हमारे जीवन में सुख और शांति हो, इसके लिए हमारे संतों का मानना है कि अगर आप जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सुख आपको सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर नहीं मिलेगा।

ऐसा इसलिए, क्योंकि संसार में क्षणिक सुख है, सुख का भ्रम है। यहां सुख नहीं है, सुख के समान कुछ आभास है। सुख केवल आध्यात्मिक जीवन में ही प्राप्त होता है। सुख का एकमात्र निवास केवल अध्यात्म के आंगन में ही होता है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है, परमात्ममय सृष्टि में त्यागभाव से संसार की वस्तुओं का उपयोग करना। जब तक मनुष्य सरल नहीं बनता तब तक उसकी पुकार परमात्मा नहीं सुनते। प्रार्थना और संगीत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रार्थना का अर्थ है, इस संपूर्ण विश्वजगत की स्वायत्तता स्वीकार करते हुए उस परमसत्ता से स्वयं को जोडने का प्रयास और संगीत का अर्थ है अपने हृदय के भावों को लालित्यपूर्ण ढंग से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास। दोनों का एक ही उद्देश्य है, प्रभु की प्राप्ति। प्रार्थना में भक्त अपने स्वयं के अस्तित्व को परमात्मा के सामने समर्पित करते हुए अपनी पुकार परमात्मा को सुनाता है और संगीत में भी भक्त अपने अंतर्मन के भावों को प्रभु को सुनाता है। इस तरह दोनों का उद्देश्य एक ही है, विधि अलग-अलग है। प्रार्थना में भक्त प्रार्थनामय हो जाता है।

प्रेम व स्नेह की ऊर्जा का संचार

मूल रूप में हम आत्मा हैं। प्रेम स्वरूप हैं। इस सत्य स्वरूप या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम असीम प्रेम व स्नेह की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। प्राणी, प्रकृति और पूरी सृष्टि के साथ अपने संबंधों को हम मधुर व स्नेह संपन्न बना सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम शाश्वत प्रेम के अर्थ को जानें, उसकी परिभाषा समझें तथा अपनी दृष्टि, वृत्ति, रुचि, स्नेह और श्रद्धा को बाह्य तत्वों से आत्मिक सत्यों की ओर मोड़ें अर्थात अपने मन, बुद्धि एवं भावनाओं को निर्मल स्नेह स्वरूप अंतरात्मा की ओर मोड़ें और इन्हें शाश्वत प्रेम के सागर परमात्मा के साथ जोड़ें। इस आत्म-परमात्म योग या आत्मिक स्नेह मिलन की अनुभूति के बाद हमें प्रेम की भावनाओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूरा जीवन ही प्रेममय हो जाएगा। क्योंकि, हम अपने आप में प्रेम ही हैं और हमारा सत्य स्वरूप और स्वाभाविक स्वभाव भी प्रेम ही है। लेकिन, कई बार हमारे अंदर का असुरक्षा भाव, दूसरों के प्रति दोष-दृष्टि, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, अपमान या आहत होने की भावनाएं हमारे असीम प्रेम के निर्मल प्रवाह को बाधित व दूषित कर देते हैं। अंदर का व्यर्थ, अस्वस्थ एवं नकारात्मक सोच व दृष्टिकोण हमारी स्नेह की कोमल भावनाओं का दमन कर देते हैं। प्रेम के स्वच्छ और शाश्वत स्रोत में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आज सच्चा प्रेम पाने या अनुभव करने के लिए हम किसी अन्य पर आश्रित हो जाते हैं। क्योंकि, आत्मिक स्नेह का मूल अंतरात्मा से तथा आत्मिक प्रेम के शाश्वत स्रोत परमात्मा से हमारी मन, बुद्धि व भावनाओं का नाता टूट गया है। इसलिए अगर हम अपने से या दूसरों से अहैतुक प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें भी उन्हें बिना किसी शर्त प्यार देना होगा। इसके लिए, हमें स्वयं को अर्थात अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा और सच्चे प्रेम को समझना होगा। साथ ही, दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं को भी महसूस करना होगा। सच्चा प्रेम कोई बाहरी स्थूल वस्तु नहीं है, जिसे जब चाहे खरीदा या बेचा जा सके या उपयोग कर परित्याग किया जा सके। सच्चा प्रेम तो हमारी अपनी प्रकृति के रूप में हमारे अंदर निहित है। उसे मात्र आध्यात्मिक ज्ञान और योग बल से जगाने की देरी है। निश्छल प्रेम वास्तव में स्वयं और सबके प्रति समानता पूर्वक आत्मिक स्नेह, दया, करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता भरी शुभ भावना व शुभकामनाओं से प्रस्तुत होने की सहज, सरल और पवित्र मानसिकता है।

खेल

बेल्जियम दौरे पर जाएगी भारतीय जूनियर अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम

कोच फ्रेडरिक सोएज के नेतृत्व में टीम ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ छह मुकाबले खेलेगी

■ विजय कुमार

नई दिल्ली। भारतीय जूनियर (अंडर-21) पुरुष हॉकी टीम जुलाई में बेल्जियम के एक्सपोजर दौरे पर जाएगी, जहां वह ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ छह उच्चस्तरीय मुकाबले खेलेगी। यह दौरा इस वर्ष होने वाले जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम हाल ही में नियुक्त मुख्य कोच फ्रेडरिक के मार्गदर्शन में इस दौरे पर उतरेगी।

इस दौरे में भारत ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगा, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेगा। 7 से 17 जुलाई 2026 तक होने वाले इन छह मैचों में से पांच मुकाबले बेल्जियम में खेले जाएंगे, जबकि दौरे का अंतिम मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ एंटवर्प स्थित Hockey Center of Excellence में आयोजित होगा।

भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद 8 जुलाई को फिर ऑस्ट्रिया से भिड़ेगा। 10 जुलाई को मेजबान बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला होगा, जबकि 13 जुलाई को जर्मनी और 14 जुलाई को एक बार फिर बेल्जियम से सामना होगा। दौरे का अंतिम मैच 17 जुलाई को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाएगा।

यह दौरा भारतीय जूनियर टीम के लिए यूरोप की मजबूत हॉकी टीमों के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का शानदार अवसर होगा। विभिन्न परिस्थितियों और अलग-अलग खेल शैलियों के विरुद्ध खेलने से खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा, जो आगामी प्रतियोगिताओं में उनके लिए उपयोगी साबित होगा। दौरे से पहले मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज ने कहा, "मैं इस समूह के साथ अपने पहले दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हूं। यह खिलाड़ियों को बेहतर ढंग से समझने, नए माहौल में उनके साथ काम करने और हमारी खेल परियोजना की नींव रखने का शानदार अवसर है। ऐसे दौरे टीम में सामंजस्य बढ़ाने, साझा समझ विकसित करने और एक मजबूत टीम पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "ये मुकाबले इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें उन परिस्थितियों के करीब ले जाएंगे जिनका सामना बड़ी प्रतियोगिताओं में करना पड़ता है। इससे हमें अपने प्रदर्शन स्तर का आकलन करने, दबाव में अपनी रणनीति लागू करने और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया को परखने का अवसर मिलेगा।"

मनसुख मांडविया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर टीम इंडिया को किया सम्मानित

गांधीनगर। मेंस वॉलीबॉल कप में भारत ने रविवार को ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस प्रदर्शन की बदौलत भारत एफआईवीबी वर्ल्ड रैंकिंग में 18 स्थान ऊपर चढ़कर 42वें पायदान पर पहुंच गया। सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाली राष्ट्रीय टीम को सम्मानित किया। कप्तान जेरोम विनिथ चार्ल्स की अगुवाई और सर्बिया के ड्रेगन मिहाइलोविच की कोचिंग वाली भारतीय टीम ने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

भारत पूल स्टेज में अजेय रहा और ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में बहरीन को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पोडियम में जगह बनाई। ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल के अलावा, भारत के शानदार प्रदर्शन से एफआईवीबी वर्ल्ड रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है। पुरुष टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 60वें नंबर से 42वें नंबर पर पहुंच गई है। अगले दिन गांधीनगर में केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से

मुलाकात की। मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ को बधाई देते हुए टीम से अपनी सफलता को आगे भी जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह मेडल ऐतिहासिक है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए। हर उपलब्धि बड़ी जिम्मेदारी और ज्यादा उम्मीदें लेकर आती है। सरकार की हर नीति, हर निवेश और हर कोशिश का मकसद हमारे एथलीट्स को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घरेलू मैदान पर पोडियम फिनिश भारतीय वॉलीबॉल की लगातार हो रही प्रगति को दिखाती है और बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की देश की बढ़ती क्षमता को भी रेखांकित करती है। ऐसा पहली बार था जब भारत ने मेंस वॉलीबॉल कप की मेजबानी की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मांडविया ने दोहराया कि सरकार का दीर्घकालिक खेल दूरदर्शिता अकादमी विकास, टैलेंट की पहचान, स्पोर्ट्स साइंस, एथलीट कल्याण और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय अनुभव पर केंद्रित है, जिसका मकसद भारत को दुनिया के प्रमुख खेल देशों में शामिल करना है। उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि ब्रॉन्ज मेडल की सफलता देश भर में वॉलीबॉल खिलाड़ियों की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, भारतीय खेल जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वह बहुत उत्साहजनक है। सरकार ने प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और एथलीट सपोर्ट सिस्टम के लिए जो इंतजाम किए हैं और जिनकी योजना बनाई जा रही है, वे हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर यह रफ्तार बनी रही, तो मुझे यकीन है कि भारत हर बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में नियमित रूप से पोडियम पर जगह बनाएगा। कप्तान जेरोम विनिथ चार्ल्स ने टीम को अपनी तैयारियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए सरकार की समर्थन प्रणाली को श्रेय दिया देते हुए कहा, हम सरकार से मिले अटूट समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं, ट्रेनिंग के माहौल, रिकवरी की व्यवस्था और कुल मिलाकर मिले समर्थन की वजह से हम पूरी तरह से अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पाए। यह ऐतिहासिक मेडल सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हर उस भारतीय का है जो स्टेडियम में मौजूद था और पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारा हौसला बढ़ाता रहा। उनके प्रोत्साहन ने हमें हर प्वाइंट के लिए लड़ने की ताकत दी।

वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल न करने पर भड़के फैंस

कोच गौतम गंभीर की लगाई क्लास, बताया 'घमंडी'

दिल्ली। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही मुकाबलों में मेजबान ने टीम इंडिया को एकतरफा मात दी। इस दौरे पर फैंस को उम्मीद थी कि यंग स्टार वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू करते दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैभव और उनके फैंस का इंटरनेशनल डेब्यू को लेकर इंतजार और बढ़ गया। फैंस का फूठा गुस्सा आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के दोनों ही मैचों में वैभव को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया। जिसके चलते सोशल मीडिया पर फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत के बड़े से बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड चकनाचूर किया है। जिसके चलते फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें आयरलैंड सीरीज के दोनों मैचों में खिलाया जाएगा। वह उनके डेब्यू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन न उनको पहले मैच में मौका मिला और न ही दूसरे में। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दोनों मैचों में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दूसरे मैच में जब कप्तान अय्यर ने प्लेइंग-11 का ऐलान किया था, तब टीम में दो प्लेयर्स का डेब्यू होना था, ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि वैभव का नाम इनमें शामिल होगा। लेकिन दोनों खिलाड़ियों के रूप में उन्होंने प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे का नाम लिया। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रिंस यादव और वॉशिंगटन सुंदर की जगह सूर्यांश शेडगे को टीम में शामिल किया गया।

सना मीर ने शाहिद अफरीदी को लताड़ा: पाकिस्तान के पुरुषों को दी सोच बदलने की नसीहत?

महिला टी20 विश्वकप 2026 में पाकिस्तान का सफर जीत के साथ खत्म हुआ। टीम ने अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 37 रन से हराया। इस मैच से पहले पाकिस्तान महिला टीम ने चार मैच गंवाए थे और लीग राउंड से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई ती। इसकी काफी आलोचना हुई थी।

हालांकि, अब पाकिस्तानी महिला टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर पाकिस्तान में महिला क्रिकेटरों की मिलने वाली नफरत का खुलकर खुलासा किया है। 40 साल की सना मीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए महिला क्रिकेटरों के खिलाफ हो रही नफरत, झूठे प्रचार और लैंगिक भेदभाव पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को भी उनके एक बयान को लेकर लताड़ लगाई है।

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक धर्मेन्द्र भदौरिया और मुद्रक रजनी कुमारी द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस D-85, सैक्टर 6, नोएडा से छपवाकर, G-582, राज नगर पार्ट- 2, पालम कालोनी, पालम-द्वारका, नई दिल्ली-110077 से प्रकाशित, संपादकीय कार्यालय- B-4/144 A, केशव पुरम, नई दिल्ली-110035

नोटः प्रकाशित सभी लेख इत्यादि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है, कोई भी कानूनी वाद-विवाद दिल्ली के न्यायालय में तय होगा। कानूनी सलाहकारः अधिवक्ता राजेश कुमार (दिल्ली हाईकोर्ट) अधिवक्ता मनीष भदौरिया (दिल्ली हाईकोर्ट)

भाजपा नेता स्व. नरेश चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में दिग्गजों ने की शिरकत

श्रद्धांजलि सभा का संचालन कर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने पढ़े पीएम मोदी समेत कई शीर्ष नेताओं के शोक संदेश

■ धर्मेन्द्र भदौरिया

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर ने रविवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भाजपा नेता स्वर्गीय नरेश चौधरी की श्रद्धांजलि सभा का मंच संचालन किया। सभा में समाज के सभी वर्गों के हजारों लोग शामिल हुए।

मंच से श्री बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी एवं उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की ओर से प्राप्त शोक संवेदना संदेश पढ़कर सुनाए। राजीव बब्बर ने मंच से दिवंगत नरेश चौधरी के संगठनात्मक योगदान को याद किया और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरेश चौधरी का असमय जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मंच से श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वर्गीय नरेश चौधरी के परिवार में पत्नी मंजू चहल, भाई एवं एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, पुत्र एवं भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री रोहित चहल, शेखर चहल और राजगुरू चहल हैं। सभा में 360 गांव पंचायत के प्रतिनिधियों ने परिजनों को पगड़ी भेंट की।

श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा जनसैलाब, शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढाढस

श्रद्धांजलि सभा मे

गणमान्य जनों, परिजनों, मित्रों और राजनीतिक साथियों ने श्री चौधरी की पत्नी मंजू चहल, छोटे भाई एवं एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, पुत्र एवं भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री रोहित चहल, शेखर चहल और राजगुरू चहल के प्रति संवेदना प्रकट की।

भजनांजलि और पगड़ी भेंट

श्रद्धेय कथा वाचक अजय भाई ने भजनांजलि अर्पित की। 360 गांव पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में पालम, नांगल, नजफगढ़, बादली, शाहपुर जाट सहित कई गांवों और चहल परिवार के पारंपरिक क्षेत्र चांदनी महल के लोगों ने परिजनों को पगड़ी भेंट की।

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश चौधरी की श्रद्धांजलि सभा रविवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुई। 19 जून को उनके आकस्मिक निधन के बाद आयोजित सभा में समाज के सभी वर्गों के हजारों लोग शामिल हुए।

पीएम मोदी का शोक संदेश पढ़ा गया

सभा में बी.एल. संतोष, रेखा गुप्ता, हर्ष मल्होत्रा सहित कई नेताओं ने मंच से श्रद्धासुमन अर्पित किए। मंच संचालन कर रहे भाजपा नेता राजीव बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गड़करी एवं उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के संवेदना संदेश पढ़े।

ये रहे मौजूद

श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, आरएसएस के राष्ट्रीय सह प्रमुख विजय जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अलोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। इनके अलावा सांसद मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, रविंद्र इंद्राज सिंह, महापौर प्रवेश वाही, दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, रमेश पोखरियाल, कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल, आप नेता अनिल झा समेत अनेक विधायक, पार्षद व पदाधिकारी शामिल हुए।

5 जुलाई को लगेगा श्री बालाजी दिव्य दरबार

दरबार में होगी विशेष पूजा-अर्चना

नई दिल्ली, संवाददाता। नरेला क्षेत्र में आगामी 5 जुलाई 2026 (रविवार) को श्री बालाजी दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। सेवादार नवीन मान और सेवादार आशीष खोखर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाला जी दिव्य दरबार का यह धार्मिक आयोजन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगा। सेवादार नवीन मान और सेवादार आशीष खोखर ने बताया कि दरबार में मेहंदीपुर बालाजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना एवं दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की गई है। सेवादार नवीन मान और सेवादार आशीष खोखर ने बताया कि हर समस्या का बालाजी के दरबार में समाधान पाएं तथा दरबार एक ही, आस्था अपार, बालाजी सब पर कृपा अपार। आगंतुक भक्तों के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बाला जी दिव्य दरबार का संचालन बाला जी के अनन्य भगत सचिन जी द्वारा किया जाएगा।

देशभर में कल से लागू होगा वीबी-जी राम-जी अधिनियम

नई दिल्ली। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम-जी) अधिनियम बुधवार से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम के देशव्यापी क्रियान्वयन से पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी वक्तव्य में कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी।

डीपीएल-3 की नीलामी: ऋषभ पंत और प्रतिका रावल पर नजरें, 600 से ज्यादा खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

विजय कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी20 के तीसरे सीजन की खिलाड़ी नीलामी बुधवार , 1 जुलाई को सुबह 9:00 बजे नई दिल्ली में होगी। आठ पुरुष और चार महिला फ्रेंचाइजी आगामी सीजन के लिए अपनी टीमों का गठन करेंगी। पुरुष और महिला वर्ग को मिलाकर 600 से अधिक खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे। इनमें 400 से अधिक पुरुष और 200 से अधिक महिला खिलाड़ी हैं। नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने 65 पुरुष और 28 महिला खिलाड़ियों को रिटेन किया है।

पुरुष वर्ग के मार्की खिलाड़ियों में ऋषभ पंत सबसे बड़ा नाम हैं। उनके अलावा ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, मयंक यादव, कुलदीप यादव, अनुज रावत, सिमरजीत सिंह, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, सार्थक रंजन, सुयश शर्मा, वंश बेदी और तेजस्वी भी नीलामी पूल में हैं। महिला वर्ग में प्रतिका रावल, प्रिया पुनिया, प्रिया मिश्रा, पारुनिका सिसोदिया और सिमरन दिल बहादुर मार्की खिलाड़ी हैं।

प्रत्येक पुरुष फ्रेंचाइजी को 1.5 करोड़ रुपये और महिला फ्रेंचाइजी को 75 लाख रुपये का पर्स दिया गया है। रिटेन खिलाड़ियों की राशि घटाकर बची रकम से टीमें बोली लगाएंगी। पुरुष वर्ग में मार्की का बेस प्राइस 10 लाख, कैटेगरी ए का 5 लाख, बी का 3 लाख और सी का 1 लाख रुपये है। महिला वर्ग में मार्की का बेस प्राइस 5 लाख, ए का 3 लाख, बी का 1.5 लाख और सी का 75 हजार रुपये रखा गया है।

पुरुष मार्की में भारत के अंतरराष्ट्रीय, इंडिया ए और पिछले तीन आईपीएल सीजन में खेले खिलाड़ी हैं। कैटेगरी ए में दिल्ली की सीनियर टीम के खिलाड़ी, बी में अंडर-23, अंडर-19, अंडर-16 और सी में डीडीसीए लीग के खिलाड़ी शामिल हैं। महिला मार्की में भारतीय अंतरराष्ट्रीय और डब्ल्यूपीएल की खिलाड़ी हैं। पुरुष टीमों को 20 से 25 खिलाड़ी रखने होंगेः 2 मार्की, 4 कैटेगरी ए, 6 से 10 बी और 8 से 9 सी। महिला टीमों में 18 से 22 खिलाड़ी होंगेः 2 मार्की, 4 ए, 7 से 8 बी और 5 से 8 सी।

आरटीएम कार्ड का इस्तेमालः हर फ्रेंचाइजी के पास एक आरटीएम कार्ड होगा। यदि पिछले सीजन का खिलाड़ी नीलामी में आता है तो मूल फ्रेंचाइजी अंतिम बोली पर मैच कर उसे वापस ले सकेगी।

डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा, नीलामी दिल्ली क्रिकेट कैलेंडर का सबसे रोमांचक दिन है। डीपीएल अब स्थापित और उभरते खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच बन चुका है। नीलामी का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार और डीपीएल टी20 के यूट्यूब चैनल पर होगा।

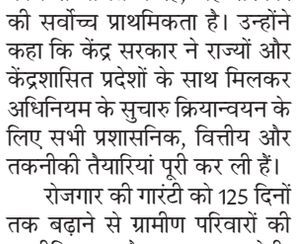

वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन: विकसित भारत की यात्रा में क्षेत्रीय उद्योगों की अहम भूमिका: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में क्षेत्रीय उद्योगों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' केवल आर्थिक प्रगति का लक्ष्य नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्रीय क्षमताओं को राष्ट्रीय ताकत में बदला जाए और स्थानीय नवाचारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक पहुंचाया जाए। रक्षा मंत्री मंगलवार को वडोदरा में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' में उद्योगपतियों, उद्यमियों, युवा इनोवेटर्स और शिक्षाविदों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषा भी मौजूद रहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में भारत की भूमिका उसकी आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और सामूहिक संकल्प से तय होगी। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र तीन प्रमुख स्तंभों, आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा, पर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास देश की सुरक्षा को मजबूती देते हैं, जबकि सुरक्षित वातावरण उद्योग और नवाचार के विकास के लिए जरूरी होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र का विकास केवल हथियारों और सैन्य तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े औद्योगिक इकोसिस्टम को गति देता है। डिफेंस कॉरिडोर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के माध्यम से देश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है।